राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 10, अंक- 266 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, शुक्रवार ,26 मार्च 2021, मूल्य रु. 1.50

एक नज़र...

श्रीलंकाई नौसेना ने भारत के 20 मछुआरों को गिरफ्तार किया

रामेश्वरम। श्रीलंकाई नौसेना ने कथित तौर पर अपने जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने को लेकर 20 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया और दो नाव जब्त कर ली। अधिकारियों ने यहां मंगलवार को यह जानकारी दी। मत्स्यपालन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उक्त मछुआरे रामेश्वरम और थंगचिमदम के रहने वाले हैं और उन्हें बुधवार की रात को श्रीलंकाई नौसेना ने कच्चतीवु के पास से पकड़ा। अधिकारियों ने बताया कि मछुआरों को जांच के लिए स्थानीय नौसैनिक शिविर में ले जाया गया है और उन्हें श्रीलंकाई मत्स्यपालन विभाग को सौंपा जा सकता है। भारत के मछुआरा संघ के प्रतिनिधियों ने श्रीलंकाई नौसेना द्वारा बार-बार तमिलनाडु के मछुआरों को गिरफ्तार करने की घटनाओं पर चिंता जताई है और केंद्र तथा राज्य सरकार से उनकी सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करने की अपील की है।

चुनाव आयोग ने बंगाल में पांच अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) सहित पांच अधिकारियों के तबादले का आदेश दिया है। आयोग ने कहा है कि इन अधिकारियों को चुनाव से जुड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाए। आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया कि तबादला किये गये अधिकारियों में पश्चिम क्षेत्र के एडीजी संजय सिंह, दक्षिण कोलकाता के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सुधीर नीलकंठ, कूच बिहार के पुलिस अधीक्षक के. कानन, डायमंड हार्बर के पुलिस अधीक्षक अविजीत बनर्जी और झाड़ग्राम की जिला निर्वाचन अधिकारी आयशा रानी शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि इन अधिकारियों के बारे में शिकायतें मिली थी और उनके तहत आने वाले क्षेत्रों से हिंसा की खबरें मिली थीं। राज्य में 27 मार्च से आठ चरणों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। आयोग ने आयशा रानी को चुनाव संपन्न होने तक मुख्य सचिव कार्यालय से संबद्ध करने का निर्देश दिया है।

आयकर विभाग ने द्रमुक नेता के ठिकानों पर की छापेमारी

चेन्नई। आयकर विभाग के अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु में द्रमुक के एक प्रमुख नेता के ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध कर चोरी के मामले में छापेमारी आज सुबह शुरू हुई। राज्य के विपक्षी दल द्रमुक के एक प्रमुख नेता के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस नेता का नाता तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई जिले से है। छापेमारी के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलना अभी बाकी है। गौरतलब है कि तमिलनाडु में छह अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और पिछले कई सप्ताह से आयकर विभाग के अधिकारी राज्य के राजनीतिक पदाधिकारियों सहित कई लोगों के यहां छापेमारी कर रहे हैं।

तेलंगाना में कर्ज से परेशान एक परिवार के चार सदस्यों ने की आत्महत्या

हैदराबाद। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में कर्ज के बोझ तले दबे एक परिवार के चार सदस्यों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कासिपेट मंडल में एक मकान में एक व्यक्ति, उनकी पत्नी, बेटी और बेटा का शव बृहस्पतिवार को पंखे से लटके पाया गया। पुलिस के मुताबिक परिवार के एक रिश्तेदार ने बताया कि व्यक्ति पिछले कई वर्षों से खेती कर रहा था और उसने कृषि भूमि पट्टे पर ली हुई थी, लेकिन हाल ही में उसकी फसल बर्बाद हो गई थी और उसने पिछले साल अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज भी लिया था। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि व्यक्ति ने कुछ लोगों से कर्ज लिया था और इस तरह वह लाखों रुपये के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। अधिकारी ने बताया कि परिवार ने संभवतः इसी कारण यह कठोर कदम उठाया।

अमित शाह का ममता पर तंज, बोले- दीदी के रहते मलेरिया नहीं जाएगा

नई दिल्ली । पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल और असम में आज शाम पांच बजे पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर बयानों के तीर चला रहे हैं। यहां के झारग्राम पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि- दीदी के रहते हुए आपको मलेरिया से छुटकारा नहीं मिलेगा। डेंगू और मलेरिया से उनकी दोस्ती है। हमारे लिए वोट करें, हम 2 साल में बीमारियों को मिटा देंगे ... एक तरफ, पीएम मोदी आदिवासी कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, जबकि दीदी अपने भतीजे के लिए काम कर रही हैं। आप किसे चाहते हैं?

शाह ने कहा कि झारग्राम हरे भरे जंगल और लाल मिट्टी की भूमि है। आदिवासी भाइयों ने वर्षों से इस भूमि की संस्कृति संजो कर रखा है। मां, माटी मानुष का नारा देकर दीदी सत्ता में तो आई, लेकिन आपके लिए कुछ नहीं किया। शाह ने कहा कि मैं आपके क्षेत्र की कठिनाइयों को जानता हूं, लेकिन कुछ कठिनाई ऐसी हैं जो पूरे बंगाल की है। दीदी

जहां जहां घूमती हैं वहां लोगों और निर्दोष आदिवासियों को डराती हैं- खेला होबे, खेला होबे। अरे दीदी आप हमें क्या डराती हो, खेला होबे से हम डर जाएंगे क्या। दीदी आपको मालूम नहीं है, बंगाल का छोटा बच्चा भी फुटबॉल खेलता है, आपके खेला होबे से कोई नहीं डरता।

झारग्राम में शाह ने कहा आप जंगल में से वन उपज चुनकर लाते हैं, उसका अच्छा दाम नहीं मिलता। हमने तय किया है कि हम 49 वन उपजों को समर्थन मूल्य देकर अच्छा दाम देने की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल में आदिवासियों को प्रमाण पत्र चाहिए होता है तो पटवारी को कट मनी देना होता है, हमने तय किया है कि आदिवासियों के लिए ऑनलाइन प्रमाण पत्र की व्यवस्था करके कटमनी को खत्म करेंगे।

दीदी भतीजे सीएम बनाने के लिए लड़ रहीं चुनाव- पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर प्रचार का काम जोर पर है। यहां के बागमुंडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके कल्याण के लिए चुनाव लड़ रहे हैं जबकि दीदी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहीं हैं।

इससे पहले मंगलवार को गोसाबा में शाह ने कहा था कि - बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के विकास के लिए 115 स्कीम बनाई हैं। ममता दीदी ने गरीबों को लूटने के लिए 115 स्कैम बनाएं हैं। गरीबों के हक का पैसा कट मनी वाले ले जाते है। इसे बंद करने का काम भाजपा की सरकार करेगी। अपने संबोधन में अमित शाह ने फिर दोहराया कि बीजेपी की सरकार राज्य में ट्ट लागू करेगी और शरणार्थियों को नागरिकता देगी।

गौरतलब है कि हाल ही में जारी बीजेपी के संकल्प पत्र सोनार बांग्ला में कई बड़े वादे किए गए। अमित शाह ने कहा कि हम सोनार बांग्ला बनायेंगे। बंगाल चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा, अवसंरचना विकास, स्वास्थ्य, उद्योग पर जोर दिया गया है। बंगाल चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में भाजपा ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत का आरक्षण देने का वादा किया है।

रेल कर्मियों ने देश भर में प्रदर्शन किया

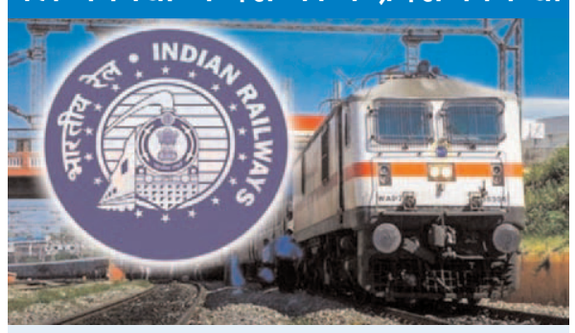

नई दिल्ली,(वेबवार्ता)। रेलवे कर्मचारियों ने भारतीय रेलवे के मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) में विभागीय यात्रा पास, आरक्षण और भविष्य निधि संबंधी सुविधाओं के उपयोग में आ रही दिक्कतों को लेकर रोष व्यक्त किया है और रेलवे बोर्ड के उच्चाधिकारियों से इन्हें दूर करने की मांग की है। ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) के आह्वान पर गुरुवार को देश भर में हर प्रतिष्ठान पर रेल कर्मचारियों द्वारा 'एचआरएमएस' के माध्यम से मिलने वाली रेलकर्मियों की सुविधाओं जैसे यात्रा पास, आरक्षण एवं भविष्य निधि में आ रही दिक्कतों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर इसे तत्काल सुधारने अथवा बंद करने की मांग की गई। एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्र ने बताया कि रेलकर्मियों एवं उनके परिवारों को पास की सुविधा, अंग्रेजो के शासन काल से प्राप्त है पर यह पहली बार हो रहा है कि उनकी सुविधा पर येन-केन प्रकारेण रोक लगाने की कोशिश हो रही है जिससे उनमें बहुत आक्रोश हैं। यहाँ तक की उनके घर शादी, बीमारी, बच्चो की पढ़ाई के लिए भविष्य निधि से रकम निकालने के आदेशों के बावजूद एचआरएमएस में आ रही दिक्कतों के कारण कर्ज लेने के लिए मजबूर हो रहे है। श्री मिश्र ने कहा कि ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन द्वारा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष इस मसले को उठाने के बाद इसे 31 मार्च 2021 तक टाल दिया गया पर इसमे अभी तक सुधार नही हुआ। इस व्यवस्था को संचालित करने वाली संस्था ''क्रिस'' ने ना तो लोगो को प्रशिक्षण दिया और ना ही उनका सर्वर ठीक तरह से काम करता है।

विधानसभा चुनावों से पहले लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद का बजट सत्र बृहस्पतिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और इस दौरान लोकसभा में 114 प्रतिशत वहीं राज्यसभा में 90 प्रतिशत कामकाज हुआ। कोविड-19 महामारी के दौरान आम बजट के पेश होने के बाद उसे पारित करने का संसद का यह एकदम नया अनुभव रहा क्योंकि सत्र के दौरान कुछ समय दोनों सदनों की बैठक अलग अलग समय पर हुई तथा सदस्यों की बैठने की व्यवस्था भी कोविड दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर की गयी। सत्र के दूसरे चरण में दोनों सदनों की बैठक एक ही समय पर होने लगीं।

सत्र की शुरूआत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति अभिभाषण के साथ हुई। हालांकि कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी पार्टियों ने तीन नये कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए राष्ट्रपति अभिभाषण का बहिष्कार किया था। बजट सत्र के पहले चरण में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। सत्र के दौरान आम बजट के साथ जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी से जुड़े विनियोग विधेयकों पर चर्चा कर उन्हें पारित किया गया।

दोनों सदनों में इस दौरान जो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किये गये उनमें वित्त विधेयक के अलावा खान और खनिज (विकास और

विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2021, बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2021 और नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021 प्रमुख हैं।

बजट सत्र में लोकसभा की 24 बैठकें हुईं जो कुल 132 घंटे तक चलीं। पीठासीन सभापति भर्तृहरि महताब ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देशानुसार और सदन के सदस्यों के सहयोग से 17वीं लोकसभा के अन्य सत्रों की भांति बजट सत्र में भी रिकॉर्ड कार्य हुआ। इस सत्र के दौरान 114 प्रतिशत कामकाज हुआ।

गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष बिरला कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण पिछले कुछ दिन से सदन की कार्यवाही संचालित नहीं कर रहे थे। महताब ने बताया कि इस बजट सत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए सभा 48 घंटे और 23 मिनट देर तक बैठी।

लोकसभा में बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी सदन में मौजूद थे। राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान हुए कामकाज का लेखाजोखा प्रस्तुत करते हुए नायडू ने कहा कि सत्र के दौरान सदन में 90 प्रतिशत कामकाज हुआ जबकि व्यवधान के चलते लगभग 21 घंटे बर्बाद हुए। उन्होंने बताया कि सत्र के पहले चरण में कामकाज 99.6 फीसदी रहा जबकि दूसरे चरण में यह 85 फीसदी रहा। उन्होंने बताया कि इस दौरान वित्त और विनियोग विधेयक सहित कुल 19 विधेयक पारित हुए।

नायडू ने कहा कि जून 2019 के बाद से सदन के कामकाज में वृद्धि हुई है। इसके परिणमस्वरूप पिछले चार सत्रों के दौरान कुल 94 प्रतिशत कामकाज हुआ। इसके लिए उन्होंने सदस्यों का धन्यवाद किया और कहा कि बगैर उनके सहयोग के यह संभव नहीं था।

इस अवसर पर सभापति ने समिति की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति का भी जिक्र किया और सभी दलों के नेताओं से सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने व समिति की बैठकों को गंभीरता से लेने का आग्रह किया।

बजट सत्र के दूसरे चरण की बैठक आठ अप्रैल तक प्रस्तावित थी और इस दौरान कुल 33 बैठकें होनी थी लेकिन निर्धारित समय से पहले ही सत्र समाप्त हो गया। इस दौरान कुल 23 बैठकें हुई। उल्लेखनीय है कि बजट सत्र की शुरुआत 29 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई थी और एक फरवरी को आम बजट पेश किया गया था। बजट सत्र का पहला हिस्सा 15 फरवरी को संपन्न होना था किंतु राज्यसभा में यह 12 फरवरी को संपन्न हुआ। लोकसभा में बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को संपन्न हुआ।

पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के लिए थमा चुनावी शोर

नई दिल्ली । पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार बृहस्पतिवार शाम को थम गया। अब शनिवार यानी 27 मार्च को दोनों ही राज्यों में पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बालीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती, सांसद व पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर, गायक एवं अभिनेता मनोज तिवारी को मैदान में उतारा था।

वहीं, तृणमूल के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे व सांसद अभिषेक बनर्जी ने ताबड़तोड़ सभाएं और रोड शो किए। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी से लेकर माकपा राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्रा भी प्रचार के लिए जुटे रहे। पहले चरण में पश्चिम बंगाल के जंगलमहल के पांच जिलों की तीस विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन तीस सीटों पर 191 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। जिन सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे उनमें बांकुड़ा की चार, पुरुलिया की नौ, झाड़ग्राम की चार, पूर्व मेदिनीपुर की सात व पश्चिम मेदिनीपुर की छह सीटें शामिल हैं।

बंगाल में पहले चरण के 30 में से सात निर्वाचन क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। बंगाल में इस चरण के लिए चुनाव लड़ रहे 191 में से 19 उम्मीदवार करोड़पति हैं। सबसे कम संपत्ति वाले दो उम्मीदवार हैं, जिनकी कुल संपत्ति 500 रुपये है। असम में 27 मार्च को 47 सीटों पर होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए 269 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पहले चरण के लिए कुल 269 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे जिनमें 10 उम्मीदवारों के कागजात रद हो गए जबकि 16 ने नामांकन वापस ले लिया था। असम में पहले चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में माजुली से मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, जोरहट से विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी, बोकाखाट से असम गण परिषद के मंत्री अतुल बोरा और कालियाबोर से केशव महंत हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रत्याशियों में गोहपुर से असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रिपुन बोरा और नाजिरा से , कांग्रेस विधायक दल के नेता देवव्रत सैकिया चुनाव लड़ रहे हैं।

श्रीनगर में सीआरपीएफ टीम पर आतंकी हमला

2 जवान शहीद, 2 गंभीर घायल

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर के बाहरी इलाके लावेपोरा में गुरुवार को कार सवार आतंकियों ने सीआरपीएफ की एक पेट्रोलिंग पार्टी के वाहन पर हमला कर दिया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए और 2 अन्य घायल हो गए। घटना के बाद अतिरिक्त बल मौके पर पहुंच गया है और इलाके की नाकेबंदी कर हमलावरों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। कश्मीर के अधिकारियों ने बताया कि यह हमला लावापोरा इलाके में हुआ है। कार में आए आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के सेमी-बुलेटप्रूफ वाहन का अचानक से रास्ता रोका और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिसमें वाहन में सवार 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 घायल हो गए। घायल जवानों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। ये हमला CRPF की 73वीं बटालियन पर किया गया है। इस हमले के बाद सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। मौके पर पुलिस और अर्द्धसैनिक बल के आलाधिकारी पहुंच चुके हैं, जिनके नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घटना के बाद इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक, हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ बताया जा रहा है।

श्रीनगर के लावापोरा इलाके में सीआरपीएफ की एक पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें दो जवान शहीद हो गए, जबकि दो जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जीएनएनसीटीडी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में आप

लोकतंत्र के लिए दुखद दिन -केजरीवाल

नई दिल्ली,(वेबवार्ता)। जीएनसीटीडी संशोधन बिल के राज्यसभा में पारित होने के घंटों बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है। उन्होंने यह भी जोर देकर कहा कि लोगों को सत्ता वापस दिलाने के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। बता दें कि सोमवार को संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया, जो उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देता है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, राज्यसभा ने जीएनसीटीडी संशोधन विधेयक पारित किया। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह दुखद दिन है। लोगों को

शक्ति वापस दिलाने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जो भी बाधाएं हैं, हम अच्छा काम करते रहेंगे। काम न तो रुकेगा और न ही धीमा होगा। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह कानून के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रही है। पार्टी ने आरोप लगाया कि ये दिल्ली सरकार को प्रशासनिक रूप से नपुंसक बनाने का एक असंवैधानिक प्रयास है। इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन कहते हुए, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, आज लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई सरकार के अधिकारों को छीन लिया गया है और एलजी को सौंप दिया गया है। विडंबना यह है कि संसद का उपयोग लोकतंत्र की हत्या के लिए किया गया, जिसे हमारे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। दिल्ली के लोग इस तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे।

बता दें कि राज्यसभा ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 को विपक्ष के भारी विरोध के बीच मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल की कुछ भूमिकाओं और अधिकारों को परिभाषित किया गया है।

पश्चिम मिदनापुर जिले में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सांसद गौतम गंभीर एक चुनाव प्रचार रैली के दौरान।

ब्रिटेन के शाही परिवार में नया मेहमानःडिलीवरी के लिए हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकीं महारानी की पोती, बाथरूम में दिया बेटे को जन्म

लदन। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ-II की पोती जारा टिंडल ने बेटे को जन्म दिया। जारा समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकीं और घर पर बाथरूम में ही डिलीवरी करानी पड़ी। बच्चे का नाम लुकास फिलिप टिंडल रखा गया है। जारा टिंडल 94 वर्षीय महारानी एलिजाबेथ की बेटी राजकुमारी ऐन और इंग्लैंड के पूर्व रग्बी खिलाड़ी माइक टिंडल की बेटी हैं।

महारानी को दसवें ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड से मिलने का इंतजार

बकिंघम पैलेस के स्पीकर ने बताया कि महारानी और ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग बच्चे के जन्म की खबर मिलने से खुश हैं और वे अपने दसवें ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड से मिलने का इंतजार कर रहे हैं।

उत्तराधिकार की लाइन में 22वें हैं लुकास

शाही परिवार के नए मेहमान लुकास फिलिप टिंडल का मिडिल नाम उनकी मां जारा के दादा राजकुमार फिलिप और माइक के अपने पिता के नाम पर रखा गया है। लुकास, ब्रिटेन के सिंहासन के उत्तराधिकारी की लाइन में 22वें नंबर पर हैं। वे जारा टिंडल की तीसरी संतान हैं। लुकास की दो बहनें मिया और लीन हैं।

71 साल बाद एक साल में सबसे कम शादियां: जापान में वेडिंग कंपनियां लड़कियों को डमी दूल्हा और बारातियों के साथ करा रहीं शादी का अहसास

टोक्यो। कोरोना महामारी ने जापानी युवाओं में शादी न करने के ट्रेंड को और तेजी से बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 2020 में पूरे देश में 5,37,583 शादियां हुईं। यह 2019 की तुलना में 12.7त्न कम है, जो 71 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। 2020 में 872,683 बच्चों का जन्म हुआ। 2019 की तुलना में 25,917 बच्चे कम पैदा हुए। बच्चों के जन्म के मामले में यह गिरावट 122 साल में सबसे अधिक है। इसकी वजह युवाओं पर बढ़ता आर्थिक दबाव है। इस वजह से जापानी आबादी सिकुड़ रही है और बूढ़ी हो रही है। शादी के घटते ट्रेंड के बीच वेंडिंग कंपनियां इनोवेटिव आइडिया लाई हैं। मिसाल के तौर पर यहां कई कंपनियां फेक शादी करा रही हैं, ताकि महिलाएं शादी की रस्मों को महसूस कर सकें और इस यादगार दिन को सहेज सकें।

इस पैकेज के तहत युवती को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। शादी की रस्में होती थी। किराए पर दूल्हा व मेहमान बुलाए जाते है। एल्बम भी बनती है। यह ब्रेन चाइल्ड आइडिया सर्का ट्रैवल कंपनी की प्रेसिडेंट युकिको इनोयु का था। वे बताती हैं कि देश के युवाओं को शादी के लिए प्रेरित करने के लिए यह पैकेज शुरू किया था। इस आयोजन से महिलाओं को सकारात्मकता मिलती है। लेकिन अब लोग बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे। वे बताती हैं कि जापान में 20-49 साल के एक चौथाई लोग कुंवारे हैं।

तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन पर क्रूर कार्रवाई: म्यांमार में सेना ने घर में घुसकर पिता की गोद में बैठी 7 साल की बच्ची को गोली मारी

यांगून। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के दमन में लगी सेना ने एक और क्रूर कार्रवाई की है। मांडले शहर में सेना ने पिता की गोद में बैठी 7 साल की मासूम को गोली मार दी। पुलिस की गोली से मरने वाली खिन मायो चित सबसे कम उम्र की पीड़ित है। मृतका के पड़ोसी सुमाया ने बताया, 'पुलिस प्रदर्शनकारियों की तलाश कर रही थी। कुछ पुलिस वाले आए और लात मारकर खिन के घर का दरवाजा खटखटाने लगे।खिन की बड़ी बहन ने दरवाजा खोला तो जवान घर में घुस गए। पूछने लगे, पापा के अलावा घर में कौन है?

बहन ने कहा- कोई नहीं। तब पुलिसकर्मी ने उसे झूठा बताकर पीटा। यह देख सामने खड़ी खिन डरकर घर में मौजूद पिता की गोद में बैठ गई। तब पीछे से आए पुलिसवालों ने पिता पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं, जो गलती से बच्ची को लग गईं। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।' बता दें कि अब तक सेना की गोलीबारी में 20 बच्चों की जानें जा चुकी हैं।

उत्तर कोरिया पर भड़का जापान: कम दूरी की दो बैलिस्टिक मिसाइलों के टेस्ट से पीएम सुगा नाराज

बोले- यह ओलंपिक और बाइडेन पर दवाब बनाने की कोशिश

टोक्यो। जापान से स्टे समुद्र में उत्तरी कोरिया ने दो बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। इसका जापान के प्रधानमंत्री योशिहदे सुगा ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक और बाइडेन सरकार पर दवाब बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश और क्षेत्र की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया जा रहा है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है।

उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र परिषद ने उत्तरी कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण करने पर बैन लगाया हुआ है। अगर इन परीक्षणों की पुष्टि होती है, तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्योंगयांग से जुड़ने के प्रयासों को एक चुनौती देगा। वहीं, इस पर इंडो-पैसेफिक कमांड ने गुरुवार को एक बयान जारी किया। उन्होंने इसे उत्तर कोरिया के अवैध हथियार प्रोग्राम का हिस्सा बताया और इसे अंतराष्ट्रीय समुदाय और पड़ोसी देशों के लिए भी खतरा करार दिया। कमांड ने कहा है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

कुछ हफ्ते पहले अमेरिका को दी थी धमकी

इससे पहले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग की बहन ने दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यासों को लेकर अमेरिका को धमकी दी थी। उन्होंने इन अभ्यासों को घुसपैठ करार दिया था। साथ ही कहा था कि अगर वह अगले चार साल शांति

से सोना चाहता है, तो किसी तरह की गड़बड़ी न करे।

जापान ने चीन के दूतावास के सामने किया विरोध प्रदर्शन

जापान ने इस परीक्षण का चीन के दूतावस सामने विरोध प्रदर्शन किया। जापान के मुताबिक, इस परीक्षण में शांति और सुरक्षा को लेकर खतरा पैदा कर दिया है। वहीं, दक्षिण कोरिया ने इस पर गहरी चिंता जताई है। जापान की सरकार के मुताबिक, एक मिसाइल 450 किलोमीटर तक गई थी और इसकी लैंडिंग जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र से सटे बाहरी इलाके में हुई। ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है।

जापान में चार महीने बाद हैं समर गेम्स, बाइडेन से मुलाकात में चर्चा करेंगे

जापानी प्रधानमंत्री योशिहदे सुगा ने कहा है कि एक साल के भीतर यह परीक्षण हुआ है। जो जापान की शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। परीक्षण ऐसे वक्त हुआ है, जब जापान में ओलंपिक मशाल रिले की शुरूआत गुरूवार को हुई है। चार महीने बाद टोक्यो में समर गेम्स होने हैं, जिन्हें कोरोना की वजह से 2020 में स्थगित कर दिया था।

सुगा ने कहा कि हम ओलंपिक को लेकर सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अगले महीने अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन से होने वाली मुलाकात में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे।

अमेरिका और दक्षिण कोरिया की इंटेलिजेंस डाटा का विश्लेषण कर रही

इसके अलावा दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ स्टाफ ने बताया कि दो अनआइडेंटिफाइड प्रोजेक्टाइल का परीक्षण समुद्र में किया। यह इलाका कोरिया के प्रायद्वीप और उत्तरी कोरिया के दक्षिण में स्थित हैमग्योंग प्रांत का है। इस मामले में दक्षिण कोरिया और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी डाटा का विश्लेषण कर रही है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया की प्रेसीडेंशियल ब्लू हाउस राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाएगा। इसमें परीक्षण को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं, जापान कोस्ट गार्ड को चेतावनी जारी की है और उन्हें किसी भी तरह की गिरी हुई वस्तु के बारे में जानकारी देने को कहा है।

अमेरिका की नीति को चुनौती

उत्तरी कोरिया ने 2017 से किसी भी तरह के न्यूक्लियर हथियार और लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली मिसाइल का परीक्षण नहीं किया है। इससे पहले 2018 में उत्तर कोरिया के तानाशाह और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 2018 में मुलाकात हुई थी।

साउथ कोरिया में अमेरिका के 28,500 सैनिक तैनात

इंडिपेंडेंट यूएन सेंक्शन मॉनिटर के मुताबिक, नॉर्थ कोरिया लगातार न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को डेवलप कर रहा है। यह 2020 के यूएन के प्रस्तावों का उल्लंघन है। इसमें साइबर हैकिंग की मदद से फंड की व्यवस्था की जा रही है। 2018 की शुरूआत में उत्तर कोरिया ने न्यूक्लियर हथियारों और मिसाइलों के परीक्षण पर रोक लगाने का एलान किया था। तब कहा गया था कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति से हुई बातचीत के बाद किसी दबाव में फैसला नहीं लिया है। अब तक उत्तरी कोरिया कई मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है। जो दक्षिण कोरिया के लिए खतरा है। वहीं, इसे देखते हुए अमेरिका ने मार्च 2020 के शुरुआत में 28,500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए हैं।

इजरायल में 2 साल में चौथी बार चुनाव:प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी बहुमत से दूर

इजरायल। इजरायल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। यहां पिछले 2 साल में 4 बार चुनाव होने के बाद भी राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है। हुए संसदीय चुनाव के बाद लगभग 90त्न मतों की गिनती हो चुकी है, लेकिन किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में 5वीं बार चुनाव की संभावना बढ़ गई है।

नेतन्याहू बहुमत से 31 सीट दूर

इजरायली संसद में 120 सीटें हैं। बहुमत के लिए यहां 61 का आंकड़ा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिक्कुड पार्टी को 30 सीटें मिली हैं। 71 साल के नेतन्याहू के नेतृत्व वाला दक्षिणपंथी गठबंधन जादुई आंकड़े से काफी पीछे है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी याईर लपिड के नेतृत्व वाली यश अटिड पार्टी को 17 सीटें मिली हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिणपंथी यमीना पार्टी नेतन्याहू के गठबंधन में शामिल हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो नेतन्याहू के गठबंधन को बहुमत के लिए सिर्फ 2 सीटों की और जरूरत पड़ेगी। उधर, यूनाइटेड अरब लिस्ट पार्टी के लीडर मंसूर अब्बास ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इजरायल में इस बार कुल 67.2 फीसद मतदान हुआ है। यह 4 चुनावों में सबसे कम है। पिछली बार 71.5 फीसद वोट पड़े थे। कुछ विशेषज्ञों ने कम मतदान की वजह बार-बार होने वाले चुनावों को माना है। वहीं, कुछ ने सप्ताह के आखिर में पड़ने वाले त्योहार को बड़ा कारण बताया है। मंगलवार शाम को आए एक्जिट पोल में भी किसी को बहुमत नहीं मिलने की बात कही गई थी।

इजरायल में चुनावी सर्वेक्षण इस बात की ओर इशारा किया गया था कि चुनाव में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू की पार्टी बहुमत से दूर रहेगी। इस सर्वे में कहा गया था कि सत्ता हासिल करने के लिए नेतन्याहू की पार्टी को छोटे दलों के भरोसे रहना होगा। छोटे दल इस बार सरकार के गठन में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इजरायल की संसद को लेकर लगातार अप्रैल 2019 से चुनाव होते रहे हैं। इसमें 2

बार चुनाव जीते राजनीतिक दलों का गठबंधन स्थायी सरकार चलाने में नाकाम रहा है। इससे पहले यहां मार्च 2020 में आखिरी चुनाव हुआ था। इस चुनाव में सरकार तो बन गई, लेकिन 6 महीने से ज्यादा ये टिक नहीं सकी। बीते स्पूतनिक से बात करते हुए न्यू होप सेंटर राइट पार्टी के उम्मीदवार रोन मोरियो के अनुसार, जल्द ही 5वी बार चुनाव हो सकता है, क्योंकि एक स्थिर सरकार बनने की उम्मीद इस बार भी कम है।

नौकरी करेंगे प्रिंस हैरी: शाही परिवार छोड़ने के बाद हैरी अब मेंटल हेल्थ प्रोजेक्ट की निगरानी करेंगे

हेल्थ टेक कंपनी में सीईओ बने

लंदन। ब्रिटेन के शाही परिवार को छोड़ आम जिंदगी गुजारने वाले ड्यूक ऑफ ससेक्स प्रिंस हैरी ने सैन फ्रांसिस्को में एक कोचिंग फर्म में बतौर चीफ इम्पैक्ट ऑफिसर (सीआईओ) ज्वॉइन किया है। 'बेटरअप' नाम के स्टार्टअप में हैरी अब एक आम कर्मचारी के तौर पर काम करते हुए नजर आएंगे। बेटरअप 2013 में स्थापित हेल्थ-टेक कंपनी है, जो पेशेवर और मानसिक स्वास्थ्य की कोचिंग मुहैया कराती है। कंपनी ने हैरी की सैलरी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन उनकी प्रोफाइलिंग जरूर बताई है।

हैरी कंपनी के मेंटल हेल्थ प्रोजेक्ट की निगरानी करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। इसके अलावा हैरी एक और सामाजिक भूमिका निभाएंगे। इसके तहत वे रुपर्ट मर्डोक की बहू कैथरीन के एस्पिन इंस्टीट्यूट में बतौर कमिश्नर गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए काम करेंगे। यह उनकी मानद सेवा होगी। इस बीच हैरी ने सीआईओ नियुक्त होने के बाद कहा- 'मैं कंपनी के मेंटल हेल्थ प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर काम करूंगा। मेरा मानना है कि हमारी मानसिक फिटनेस को प्राथमिकता देने से कई ऐसे अवसर खुल जाते हैं, जिनके बारे में हमें मालूम भी नहीं होता। इसी तथ्य को रॉयल मरीन कमांडो कहते हैं- यह मन की स्थिति है और ये हम सभी में होती है। यही सेल्फ-ऑप्टिमाइजेशन है। इसका मतलब होता है- अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम दोहन करना। सीआईओ होने के नाते मेरी जिम्मेदारी यही है कि मैं ऐसे माहौल को निर्मित करने में योगदान दे सकूं ताकि लोग अपना सबसे अच्छा वर्जन आसानी से बन सकें।'

हैरी की नियुक्ति पर कंपनी के सीईओ एलेक्सी रोबिचाक्स के अनुसार, बेटरअप टीम के सदस्य के तौर पर हैरी दुनियाभर में मानव क्षमता को बढ़ाने पर जोर देंगे। बेटरअप एप बेस्ड कोचिंग, परामर्श और सलाह के मामले में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। हैरी इसके पहले नेटफ्लिक्स, स्पॉटीफाई जैसे ओटीटी प्लेटफार्म पर पॉडकास्ट और प्रोग्राम होस्ट कर चुके हैं। बेटरअप 12,556 करोड़ की नेटवर्थ वाली हेल्थ टेक कंपनी है। कंपनी में 270 कर्मचारियों के साथ करीब दो हजार कोच हैं, जो मानसिक सेहत की ट्रेनिंग देते हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, शेवरॉन, मार्स, वॉर्नर मीडिया जैसी दिग्गज कंपनियां इनकी सेवाएं लेती हैं। सीईओ के मुताबिक कर्मचारी के बेहतरी और विकास पर केंद्रित कोचिंग की मांग पिछले एक साल में काफी बढ़ी है और हमने करीब 900 करोड़ जुटाए हैं।

कोरोना दुनिया में: ब्राजील में मौत का आंकड़ा 3 लाख के पार; बीते दिन ब्राजील के बाद अमेरिका और भारत में 50 हजार से ज्यादा केस मिले

वाशिंगटन। दुनिया में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित देश ब्राजील में महामारी की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच गया है। बीते दिन यहां 2244 लोगों की मौत हुई और अब तक संक्रमण की वजह से कुल 3 लाख एक हजार 87 लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील के अलावा अमेरिका में महामारी की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, यहां 5.58 लाख लोग जान गंवा चुके हैं।

वहीं, दुनिया में रोजाना मिलने वाले केसों में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 90 हजार से ज्यादा नए केसों के साथ ब्राजील पहले, 60 हजार से ज्यादा मामलों के साथ अमेरिका दूसरे और 53 हजार से ज्यादा केसों के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। स्टेट काउंसिल की कोविड-19 रिस्पोंस इंटर एजेंसी टास्क फोर्स के नए आंकड़ों के अनुसार 22 मार्च तक पूरे चीन में कोविड-19 वैक्सीन के 8 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने टास्क फोर्स का हवाला देते हुए कहा कि देश की आबादी में लगातार वृद्धि हो रही है। अगले चरण में, कोविड-19 से हायर रिस्क वाले लोगों को फ्री वैक्सीन देने की योजना बना रहा है। जो अब तक का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम होगा।पिछले 24 घंटे में दुनिया भर में 5.83 लाख लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इस दौरान 10 हजार से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई। दुनिया में अब तक 12.54 करोड़ लोग महामारी की चपेट में आ चुके हैं। 10.12 करोड़ लोग रिकवर हुए और 27.56 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल 2.13 करोड़ मरीज कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। ये आंकड़ेwww.worldometers.info/coronavirus के मुताबिक हैं।

शिकागो नगर परिषद में सीएए के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव गिरा, की गई थी भारत की आलोचना

वाशिंगटन। एक शिकागो नगर परिषद ने उस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है जिसमें संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) एवं मानवाधिकार के मुद्दे पर भारत की आलोचना की गई थी। प्रस्ताव को 18 के मुकाबले 26 मतों से खारिज कर दिया गया। महापौर लोरी लाइटफुट ने बुधवार को पत्रकारों से कहा, 'परिषद के कई सदस्य प्रस्ताव का समर्थन करने में असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि भारत में वास्तव में क्या हो रहा है।' बता दें कि अमेरिका में न्यूयार्क के बाद शिकागो नगर परिषद सबसे शक्तिशाली नगर परिषदों में से एक है। महापौर ने एक सवाल के जवाब में कहा, -नगर परिषद में प्रस्ताव को लेकर जो आपने अनिच्छा देखी उसकी वजह यह थी कि कई सदस्यों का मानना है कि मामले पर पर्याप्त जानकारी नहीं है।' उन्होंने कहा कि शिकागो के सामने अपनी ही कई समस्याएं हैं। लाइटफुट ने कहा, 'मैं यह कहना चाहूंगी कि शिकागो के महापौर पद पर बैठकर बाइडन प्रशासन से आगे नहीं जा सकती। इस तरह के मुद्दों पर किसी तरह की टिप्पणी और निर्णय लेने का अधिकार संघीय सरकार को है।

तख्तापलट से अमेरिका नाराज: म्यांमार पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी, सेना के कंट्रोल वाली दो कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर सकता है यूएस

यांगून। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट और बर्बर कार्रवाई से अमेरिका नाराज है। जल्दी ही अमेरिका म्यांमार सेना की तरफ से नियंत्रित की जा रही दो कंपनियों पर प्रतिबंध लगा सकता है। सूत्रों के हवाले से रायटर्स ने बुधवार को बताया कि जल्दी ही अमेरिका ट्रेजरी म्यांमार इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन (स्वाष्ट) और म्यांमार इकोनॉमिक होल्डिंग्स लिमिटेड (स्वाश) को ब्लैकलिस्ट कर सकता है। साथ अमेरिका में उनकी संपत्तियों को भी फ्रीज कर सकता है। इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और कनाडा म्यांमार सेना के जनरलों पर प्रतिबंध लगा चुके हैं।

फरवरी में हुआ था तख्तापलट

इससे पहले म्यांमार की सेना ने फरवरी के शुरुआत में तख्तापलट कर दिया था। साथ ही नोबेल प्राइज विजेता और पूर्व प्रधानमंत्री आंग सान सूकी को गिरफ्तार कर लिया था। आंग सान सूकी की पार्टी नवंबर 2020 में चुनाव जीती थी। इस पर सेना ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था। हालांकि, इलेक्शन ऑब्सर्बर ने इस तरह की किसी भी तरह की धांधली को नकारा था।

अब तक 275 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है

वहीं, सेना की दमन नीति के खिलाफ पूरे देश में सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसमें अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 11 फरवरी को एक आदेश जारी किया था। इसके तहत म्यांमार सेना पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। अब अमेरिका म्यांमार की सेना के व्यापारिक हित पर भी रोक लगा सकता है।

म्यांमार की इकोनॉमी पर सेना का कंट्रोल: म्यांमार की अर्थव्यवस्था पर सेना का नियंत्रण है। इसमें शराब, सिगरेट से लेकर टेलीकॉम, रियल स्टेट, माइनिंग भी शामिल है। वहीं, एक्टिविस्ट की मांग है कि सेना को होने वाले रेवेन्यू पर चोट पहुंचाना जरूरी है। इसमें ऑयल और गैस के बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इससे म्यांमार की सेना को बड़ा फायदा होता है। वहीं, व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ट्रेजरी डिपार्टमेंट से पूछताछ की है। हालांकि अभी इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया है।

सेना ने 628 प्रदर्शनकारियों को रिहा किया: तख्तापलट के विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए 628 प्रदर्शनकारियों को सेना ने रिहा कर दिया है। इन सभी को पिछले महीने सेना ने पकड़कर जेल में डाल दिया था। रिहा किए प्रदर्शनकारियों में अधिकतर युवा है। रिहा होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने तीन उंगलियां भी दिखाई जो सेना के विरोध का प्रतीक बन चुका है। दरअसल, पिछले साल नवंबर में म्यांमार में आम चुनाव हुए थे। इनमें आंग सान सू की पार्टी ने दोनों सदनों में 396 सीटें जीती थीं। उनकी पार्टी ने लोअर हाउस की 330 में से 258 और अपर हाउस की 168 में से 138 सीटें जीतीं। म्यांमार की मुख्य विपक्षी पार्टी यूनियन सॉलिडैरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी ने दोनों सदनों में मात्र 33 सीटें ही जीतीं। इस पार्टी को सेना का समर्थन हासिल था। इस पार्टी के नेता थान हिते हैं, जो सेना में ब्रिगेडियर जनरल रह चुके हैं। नतीजे आने के बाद वहां की सेना ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। सेना ने चुनाव में सू की की पार्टी पर धांधली करने का आरोप लगाया। इसे लेकर सेना ने सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति और चुनाव आयोग की शिकायत भी की। चुनाव नतीजों के बाद से ही लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार और वहां की सेना के बीच मतभेद शुरू हो गया। अब म्यांमार की सत्ता पूरी तरह से सेना के हाथ में आ गई है। तख्तापलट के बाद वहां सेना ने 1 साल के लिए इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया है।

एक नजर

हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दी राहत, दो साल की सजा हुई निलंबित

नई दिल्ली । आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोमनाथ भारती को दी गई दो साल की सजा को हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया है। न्यायमूर्ति सुरेश कैथ ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए 20 मई तक दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। भारती ने निचली अदालत द्वारा दी गई दो साल की सजा को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। चुनौती याचिका में कहा गया है कि राउज एवेन्यू की विशेष अदालत का फैसला राजनीति से प्रेरित है। याचिका में मांग की गई थी कि निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाकर सजा को निलंबित किया जाए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सुरक्षाकर्मियों से मारपीट करने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दी गई दो साल की सजा को मंगलवार को विशेष सत्र अदालत ने बरकरार रखने का आदेश दिया था। 22 जनवरी को मजिस्ट्रेट अदालत ने भारती को दोषी ठहराते हुए 23 जनवरी को सजा सुनाई थी। मजिस्ट्रेट के फैसले को भारती ने राउज एवेन्यू की विशेष सत्र अदालत में चुनौती दी थी।सोमनाथ भारती व अन्य के खिलाफ नौ सितंबर 2016 को एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने हौजखास थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। सुरक्षा अधिकारी का आरोप था कि भारती अपने करीब 300 समर्थकों के साथ घटनास्थल पर पंहुचे और वहां बनी दीवार को तोड़ दिया था। इसके साथ ही कर्मचारियों के साथ मारपीट कर हंगामा किया था।

सौर ऊर्जा से चलने वाली रोगाणुनाशक प्रणाली करेगी कोरोना संक्रमण से बचाव

नई दिल्ली । जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोधकर्ताओं ने दूर-दराज के इलाकों में कोविड-19 संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए सोलर पावर्ड सेल्फ जेनरेटिंग डिसिन्फेक्शन सिस्टम तैयार किया है। इसका प्रयोग बैंक, स्कूल, मॉल, मैरिज हॉल आदि में किया जा सकता है। इस आविष्कार को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय के आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित किया गया है जबकि अभी पेटेंट मिलना बाकी है। जामिया के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभाग प्रमुख प्रो. मोहम्मद इमरान खान और अस्सिटेंट प्रोफेसर डॉ ओसामा खान ने संयुक्त रूप से इस सौर ऊर्जा संचालित रोगाणुनाशक प्रणाली का आविष्कार किया है।

शोधकर्ताओं के मुताबिक, इस आविष्कार का मुख्य उद्देश्य, बड़े समारोह, सार्वजनिक या दूर-दराज के इलाकों में सौर ऊर्जा से चलने वाले सेल्फ जेनरेटिंग डिसिन्फेक्शन के जरिए कोविड -19 या इसी तरह की अन्य बीमारियों को फैलने से रोकना है। दूर-दराज के इलाक़ों में जहां बिजली कटौती आम बात है, वहां यह रोगाणुनाशक आविष्कार कोविड-19 या उस जैसी अन्य बीमारियों पर क़ाबू पाने में कारगर साबित होगा।

ऐसे करता है काम- शोधकर्ताओं के मुताबिक, यह सौर उपकरण पीवी मॉड्यूल, चार्ज रेगुलेटर, इन्वर्टर और बैटरी सिस्टम से लैस होगा जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक रोगाणुनाशक जनरेटर एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। इसके चैम्बर के अंदर से कीटाणुनाशक फुहार निकलेगी जो वहां से गुजांने वाले व्यक्तियों की किसी भी हानिकारक संक्रमण या बैक्टीरिया से रक्षा करेगी।

उपकरण को भीड़ वाले सभा स्थल के प्रवेश द्वार पर लगा दिया जाएगा। यह बहुत ही सरल, ईको फ्रैंडली, नॉन टॉक्सिक उपकरण है। इसमें किसी तरह की जटिलता नहीं है। इसे संचालित करने के लिए थोड़ी मात्रा में पानी की जरूरत होगी और दूसरी रोगाणुनाशक प्रणालियों की तुलना में अपने आप में समग्र और कम लागत वाली प्रणाली है।

दिल्ली मेट्रों में बड़ी लापरवाही, यात्री नहीं कर रहे शारीरिक दूरी के नियम का पालन

नई दिल्ली । देश की राजधानी दिल्ली में फिर कोरोना संक्रमण का दौर लौटने लगा है। यहां लगातार दूसरे दिन 1000 से अधिक मामलों का आना चिंता की बात है, लेकिन इन सबके बीच लोगों की लापरवाही जारी है। दिल्ली मेट्रो स्टेशनों के बाहर लगी कतारों में लोग एक-दूसरे से सटकर खड़े देखे जा सकते हैं। बृहस्पतिवार शाम को केंद्रीय सचिवालय, राजीव चौक व पटेल चौक समेत कई स्टेशनों के बाहर ऐसा ही नजारा देखने को मिला। अगर ऐसी ही लापरवाही बढ़ती रही तो कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी। दिल्ली मेट्रो के नियमित यात्री केशवपुरम के रहने वाले यात्री राकेश कुमार का कहना है कि इन दिनों वह जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। स्टेशनों के अंदर भी थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हो रही है, वहीं राजीव चौक से मयूर विहार जाने वाली कविता ने कहा कि उन्हें दिल्ली के जाम से बचने के लिए मेट्रो में सफर करना होता है, जो उनके लिए खतरनाक है। लोग शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मेट्रो प्रबंधन को सख्ती दिखानी होगी।

मध्य जिला प्रशासन कोरोना के बढ़ते केस को लेकर सतर्क है। इसके चलते करोलबाग, चांदनी चौक और पहाड़गंज के बाजारों में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के चालान किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि एक दिन में एक बाजार में औसतन 600 से अधिक चालान किए जा रहे हैं। बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम मेट्रो स्टेशनों के साथ ट्रेनों में सफर करने के दौरान भी मास्क नहीं लगाने और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर 200 रुपये जुर्माना लगाता है। यूं तो दिल्ली के बाजारों और मॉल के साथ नियम तोड़ने पर 2000 रुपये का प्रावधान है, लेकिन दिल्ली मेट्रो रेल निगम 200 रुपये ही जुर्माना वसूलता है।

दिनदहाड़े बदमाशों ने मां-बेटे से हथियार के बल पर लूटी चेन, लोग पुलिस सुरक्षा पर उठा रहे सवाल

नई दिल्ली । शाहदरा इलाके में दिनदहाड़े बदमाशों ने घर के बाहर हथियार के बल पर मां-बेटे के गले से चेन लूट ली। वारदात के वक्त पीड़ित पार्क से बैडमिंटन खेलकर बुलेट से घर के बाहर पहुंचा ही था, पहले से उसका पीछा कर रहे मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने मौका मिलते ही उसे घेर लिया। शोर सुनकर घर के अंदर से महिला अपने बेटे को बचाने के लिए आगे आई तो बदमाशों ने उनकी कनपटी पर पिस्टल तान दी और गले से चेन लूट ली। दोनों के गले से चेन लूटने के बाद बदमाश बड़े ही आराम से मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुट गई है।

पुलिस के अनुसार अर्चित भाटी अपने परिवार के साथ बलबीर नगर में रहते हैं। उनका खुद का कारोबार है। मंगलवार सुबह वह इलाके के एक पार्क में बैडमिंटन खेलने के लिए गए थे, दस बजे करीब वह पार्क से मोटरसाइकिल से घर के बाहर पहुंचे। उनका पीछा कर रहे एक मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने भी अपनी मोटरसाइकिल उनके बराबर में रोक दी।

अर्चित ने उनकी ओर देखा और अनदेखा कर दिया, वह मोटरसाइकिल से उतर ही रहे थे। तभी एक बदमाश ने उनपर पिस्टल तान दी, दूसरे ने उनकी गर्दन पकड़कर जमीन पर लेटा दिया और चेन लूट ली। शोर सुनकर जब युवक की मां कृष्णा भाटी अपने बेटे को बचाने आई तो बदमाश ने उनपर भी पिस्टल तान दी। उन्होंने बेटे को उठाने की कोशिश की तो बदमाश ने धक्का देकर उनके गले से चेन लूट ली। युवक की पत्नी घर के छज्जे से मदद के लिए चिल्लाई तो बदमाश ने उसकी ओर भी पिस्टल तान दी। वारदात के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। युवक की कमर में चोटे आई हैं। इस वारदात से पूरा परिवार दहशत में है, परिवार और इलाके के लोग पुलिस सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं।

राज्यसभा से बिल पास होने पर गुस्से में आप दिल्ली मे फिर खिचेंगी तलवारें

नई दिल्ली । उपराज्यपाल के अधिकारों को बढ़ाने वाला विधेयक बुधवार को राज्यसभा से भी पास हो जाने के बाद अब दिल्ली की सत्ता में टकराव की आशंका बढ़ गई है। इस विधेयक के पास होने के बाद अब सारी शक्तियां उपराज्यपाल के पास चली जाएंगी। यहां तक कि विधानसभा में प्रस्ताव या विधानसभा की समितियों को भी कार्रवाई के लिए उपराज्यपाल से अनुमति देनी होगी।

वहीं, आदमी पार्टी ने अपने तेवरों से साफ कर दिया है कि वे चुप होकर बैठ जाने वालों में शामिल नहीं हैं। विधेयक पास हो जाने के बाद जिस तरह से आप सरकार की तीखी प्रतिक्रिया आई है। उससे साफ हो रहा है कि दिल्ली में पहले वाले हालात दिखाई देंगे। दिल्ली की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो आम आदमी पार्टी 2013 में पहली बार 49 दिन सत्ता में रही थी। उसके बाद 2015 में हुए चुनाव में पूर्ण बहुमत से सत्ता में जरूर आई थी। मगर सरकार के 2018 तक महत्वपूर्ण करीब तीन साल टकराव में ही खराब हो गए थे। सरकार में काम ठप हो गया था।

अधिकारी मंत्रियों की बैठकों में नहीं जाते थे। विभाग प्रमुख फाइलें सीधे उपराज्यपाल के पास भेजते थे। विभाग के मंत्री को पता भी नहीं होता था कि फलां फाइल कहां है। उस समय यह अंदेशा लगाया जाता था अब अगले दिन किस मुद्दे पर विवाद होगा। उस समय दिल्ली सरकार अपने को पूरी सरकार मानती थी और उपराज्यपाल कार्यालय कहता था कि हम से स्वीकृति लो। ऐसे माहौल में नौकरशाही बीच में पिस रही थी। ऐसे में जो अधिकारी पाले के इधर या उधर दिखे, उन्हें भी किसी न किसी तरह से परेशानी उठानी पड़ी थी। उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ने के बाद अब टकराव की पूरी संभावना है। हालांकि पिछले कुछ माह में देखें तो दिल्ली की सरकार भी अब टकराव से बच रही थी। क्योंकि दिल्ली में सभी काम हो रहे थे। उपराज्यपाल कार्यालय से भी सरकार को सहयोग मिल जा रहा था। पिछले तीन सालों में सरकार की कोई बड़ी योजना नहीं रुकी है। मगर अब ऐसा नहीं माना जा रहा है।

दिल्ली पुलिस की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक कुख्यात बदमाश को छुड़ा ले गए साथी, एनकाउंटर में एक ढेर

नई दिल्ली । मशहूर हरियाणवी गायिका हर्षिता दहिया के हत्यारोपित गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी गिरोह के शातिर बदमाश कुलदीप उर्फ फज्जा को उसके साथियों ने दिल्ली में दिनदहाड़े छुड़ा लिया है। पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में हुई इस घटना के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच कई राउंड फायरिंग भी हुई है। मुठभेड़ में जो बदमाश मरा है, उसका नाम रवि है। इसपर कई मुकदमे दर्ज थे। जो घायल हुआ है उसका नाम अविनाश है। ज्वाइंट सीपी आलोक कुमार ने बताया कि पूरी वारदात बृहस्पतिवार को 12 बजकर 30 मिनट की है। इस दौरान बदमाशों को काबू करने के लिए पुलिस की ओर से 12 गोलियां चलाई गई हैं। फिलहाल बदमाशों की स्कोर्पियों कार को पुलिस कब्ज़े में लेकर जांच कर रही है। किसकी कार है? अभी यह पता नहीं चला है।

बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस नामी बदमाश कुलदीप उर्फ फज्जा को जीटीबी अस्पताल में मेडिकल के लिए लाई थी। इसी दौरान यहां पर कार से आए बदमाशों ने पुलिस की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया। इसके बाद कुलदीप को कस्टडी से छुड़ाने के लिए बदमाश गेट नम्बर 7 से पैदल बाहर भाग निकले। यह भी जानकारी सामने आई है कि अस्पताल के बाहर बदमाशों ने मोटरसाइकिल लूटी और उससे फरार हो गए। वहीं, सूत्रों की मानें तो एक बदमाश मुठभेड़ में मारा गया है और एक घायल हुआ है। जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है। 5 से 8 बदमाश कुलदीप को छुड़ाने आए थे। अब पुलिस कुलदीप समेत सभी बदमाशों की तलाश में जुट गई है।

पिछले साल तीन मार्च की रात दिल्ली पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ गोगी के साथ ही कुलदीप उर्फ फज्जा को गुरुग्राम से धर दबोचा था। इस दौरान रोहित उर्फ मोई एवं कपिल उर्फ गौरव को भी गुरुग्राम के सेक्टर-83 इलाके की एक सोसायटी से गिरफ्तार किया गया था।

इससे पहले वर्ष 2015 में हत्या एक मामले में फरार चल रहे 75 हजार के इनामी बदमाश कुलदीप उर्फ फज्जा को अलीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कुख्यात गैंगस्टर जोगिंद्र उर्फ जोगी का शार्पशूटर कुलदीप ने आजादपुर मंडी के पास एंटी गिरोह के एक सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी में वह गिरफ्तार हुआ था।

दिल्ली पुलिस की मानें तो बदमाश कुलदीप दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी की पढ़ाई कर चुका है। कॉलेज के दिनों में ही वह कुख्यात बदमाश जोगेंद्र उर्फ जोगी के संपर्क में था और फिर धीरे-धीरे वह गैंग का अहम सदस्य बन गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद कुलदीप कुख्यात बदमाश जोगेंद्र के साथ अपराध की घटनाएं अजाम देने लगा। वह विरोधी गिरोह के कई बदमाशों पर अब तक जानलेवा अटैक कर चुका है।

गर्भपात कराने से नाराज दामाद ने ससुराल वालों को दिया थैलियम जहर, सास व साली की मौत

नई दिल्ली । दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में पत्नी के गर्भपात करवाने से नाराज पति ने ऐसा खूनी तांडव किया कि दो लोगों की जान चली गई, जबकि एक की हालत गंभीर है। दरअसल इस शख्स ने पत्नी समेत उसके परिवार के चार सदस्यों को थैलियम जहर देकर मौत की पटकथा लिखी। घटना में आरोपित पति की सास अनीता व साली प्रियंका शर्मा की मौत हो गई, जबकि पत्नी दिव्या जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। ससुर देविंदर पर भी अब जहर का असर होने लगा है, फिलहाल वह निगरानी में हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर ग्रेटर कैलाश पार्ट-1 निवासी आरोपित पति वरुण अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जांच की कड़ी में आरोपित वरुण अरोड़ा के घर से छोटी कांच की बोतल में मौजूद थैलियम जहर बरामद कर लिया है। साथ ही उसका मोबाइल व लैपटाप भी जब्त कर लिया है।

इंटनरेट पर तलाशा था जहर का नाम

वरुण ने पुलिस को बताया कि वह ससुराल वालों को मारने की साजिश पिछले काफी समय से रच रहा था। इंटरनेट मीडिया पर वह जहर के बारे में सर्च कर रहा था। इसी दौरान उसने इराक के तानाशाह रहे सद्दाम हुसैन के बारे में एक किताब पढ़ी। किताब में इस बात का जिक्र है कि सद्दाम हुसैन अपने विरोधियों को मारने के लिए थैलियम जहर का इस्तेमाल करता था और यहीं से उसने वारदात को अंजाम देने की सोची।

जानकारी के मुताबिक आरोपित की सास अनीता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने के बाद सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने खून की जांच में पाया कि अनीता को किसी ने थैलियम जहर दिया है। धीरे-धीरे यह जहर पूरे शरीर में फैल गया और 22 मार्च को

अनीता की मौत हो गई। मामला संगीन लगने के बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई।

मछली खिलाने के साथ दिया था जहर- ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए एसएचओ इंद्रपुरी सुरेंद्र सिंह और नारायणा के इंस्पेक्टर प्रमोद के नेतृत्व में टीम बनाई गई। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि देविंदर की छोटी बेटी प्रियंका की मौत बी एल कपूर अस्पताल में 15 फरवरी को हो गई थी। साथ ही बड़ी बेटी दिव्या, देविंदर व घरेलू सहायिका भी बीमार हैं। सभी को थैलियम जहर दिया गया है। छानबीन के दौरान पुलिस को पता चला कि जनवरी के अंत में वरुण इंद्रपुरी आया था और पार्टी देने के नाम पर अपने ससुराल वालों को मछली खिलाई थी। इसके बाद टीम का संदेह वरुण पर गया। पुलिस ने वरुण को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पहले वह पुलिस को उलझाने का प्रयास करने लगा लेकिन बाद में उसने अपना गुनाह कुबूल कर लिया।

गर्भपात कराने से था नाराज- पुलिस पूछताछ में वरुण ने बताया कि उसकी पत्नी दिव्या पिछले वर्ष गर्भवती थी और उसको लग रहा था कि बच्चे के रूप में उसके पूर्वज जन्म लेंगे। वहीं, इस दौरान दिव्या को कई परेशानियां होने लगी और चिकित्सकों की सलाह पर उसने गर्भपात करा लिया। इससे दोनों के बीच झगड़ा हुआ और हालत यह हो गई कि दिव्या अपने जुड़वा बेटा-बेटी के साथ मायके आ गई। वहीं पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि वरुण का किसी महिला के साथ चक्कर चल रहा है और इसी कारण उसने ससुराल वालों को मौत की नींद सुलाने की साजिश रची। पुलिस अब दोनों पक्षों के बयान की जांच में जुट गई है।

ससुराल में पार्टी देने के नाम पर वरुण ने मछली मंगाई थी और मछली उसने न तो खुद खाई और न ही अपने दोनों बच्चों को खाने दिया। उसने खुद दांत दर्द का बहाना बनाकर मछली खाने से असमर्थता जता दी।

एक महीने से वेंटीलेटर पर है दिव्या

वरुण की पत्नी दिव्या सर गंगाराम अस्पताल में पिछले एक महीने से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। वह वेंटीलेटर पर है और बातचीत करने की हालत में नहीं है। वहीं, वरुण के ससुर देविंदर ने कम मात्रा में मछली खाई थी इस कारण उनपर अब असर दिखाई देने लगा है। उनके बाल उड़ने शुरू हो गए हैं। उनका इलाज घर पर ही चल रहा है। वहीं, घरेलू सहायक पहले आरएमएल अस्पताल में भर्ती हुई बाद में उसके स्वजन कोलकाता लेकर चले गए।

क्या है थैलियम जहर- चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ संदीप दहिया ने बताया कि थैलियम धीमा जहर है। यह सबसे पहले नर्वस सिस्टम पर वार करता है। साथ ही इससे कमजोरी, डायरिया, बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं।

नगर निगम को फंड जारी करने को लड़ाई पहुंची कोर्ट, 31 मार्च तक जारी करने का आया आदेश

नई दिल्ली । हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि 31 मार्च से पहले तीनों निगमों का पैसा जारी किया जाए। कोर्ट ने कहा कि नगर निगमों के लिए सरकार ने जो 2020-21 के बजट में प्रविधान किया था, वह पैसा जारी करना होगा। पैसों के लिए पूर्वी दिल्ली निगम की तरफ से याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई पांच अप्रैल के लिए टाल दी गई है। आदेश दिया गया है कि अगली सुनवाई पर अदालत के आदेशों की पालना रिपोर्ट दाखिल करें। पांच अप्रैल को ही पेंशन और वेतन की मांग को लेकर दायर अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई होनी है। दिल्ली सरकार को पूर्वी दिल्ली निगम को जहां 864.8 करोड़ रुपये का भुगतान करना था। वहीं, दक्षिणी निगम को 405.2 करोड़ व पूर्वी निगम को 764.8 करोड़ रुपये देने हैं। पूर्वी निगम की तरफ से अदालत को बताया गया कि अभी तक 501 करोड़ रुपये ही दिए गए हैं, जबकि करीब 364 करोड़ रुपये बकाया है। वहीं, निगमों को बकाया फंड जारी करने के सबंध में हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भाजपा ने भी दिल्ली सरकार से तुरंत फंड जारी करने की मांग की है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्र ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से यह साबित हो गया है कि इस मुद्दे पर भाजपा का आंदोलन सही है। निगम कर्मचारियों की वेतन की समस्या व नागरिक सुविधाओं को लेकर लोगों को हो रही परेशानी के लिए आप सरकार जिम्मेदार है।

पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि निगमों का लगभग 13 हजार करोड़ रुपया सरकार के पास बकाया है। बकाया फंड के लिए हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं हैं। एक याचिका वर्तमान वित्त वर्ष के फंड को जारी करवाने की मांग को लेकर थी।

सुप्रीम कोर्ट का हरियाणा और पंजाब सरकार को आदेश, दिल्ली को दें पानी

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दिल्ली जल बोर्ड की याचिका पर सुनवाई के दौरान पंजाब और हरियाणा सरकार के साथ भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड को आदेश दिया है कि जितना पानी हरियाणा पहले से दिल्ली को दे रहा है उतना पानी देता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने प्रदूषित व कम पानी देने का आरोप हरियाणा सरकार पर लगाया है, इस पर हरियाणा सरकार ने कहा कि हम दिल्ली को पर्याप्त पानी दे रहे हैं। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि हरियाणा से जो पानी भेजा जा रहा है उसमें अमोनिया की मात्रा ज्यादा है।

जवाब में दिल्ली सरकार ने कहा कि हरियाणा से पानी पूरे मात्रा में नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट चाहे तो कोर्ट कमिशनर नियुक्त कर मामले की जांच की जा सकती है। इस पर कोर्ट ने कहा अगर जरूरत पड़ी है तो हम वो भी करेंगे।

बता दें कि दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार का कहना है कि हरियाणा पर्याप्त जल की आपूर्ति नहीं करता, वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि हरियाणा दिल्ली को पूरा पानी देता है। ऐसे में दोनों सरकारों के बीच मामला उलझा हुआ है। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में दिल्ली में जल संकट हो सकता है। या फिर पानी की कमी हो सकती है।

दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली में पड़ने वाली यमुना नदी में प्रदूषण के लिए भी हरियाणा को जिम्मेदार बताती रहती हैं। उधर, हरियाणा में सत्तासीन भारती जनता पार्टी सरकार का कहना है कि दिल्ली में यमुना को दूषित दिल्ली की इंडस्ट्रियां करती हैं। हरियाणा की ओर से दिल्ली को हर रोज 1133 क्यूसेक पानी की सप्लाई की जाती है। उधर, दिल्ली सरकार की ओर से हरियाणा पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि हरियाणा सिर्फ 479 एमजीडी पानी ही उसको मुहैया करा रहा है जबकि 609 पानी की जरूरत दिल्ली को हर रोज होती है।

जल बोर्ड का आरोप यह भी है कि उसको कैरीड लाइन चैनल के जरिए 549 क्यूसेक और दिल्ली सब ब्रांच से 306 पानी क्यूसेक पानी ही सप्लाई होता है। यह हथनीकुंड व मुनक नहर के साथ-साथ भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के जरिए दिल्ली को सप्लाई किया जाता है।

वहीं हरियाणा का यह भी दावा करता रहा है कि वह हर रोज 120 क्यूसेक पानी यमुना के जरिए भी दिल्ली को मुहैया कराता रहा है।

क्या अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है किसान आंदोलन? सिंघु बॉर्डर बयां कर रहा हकीकत

नई दिल्ली । संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को किसान आंदोलन के चार महीना पूरा होने पर सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक भारत बंद का एलान किया है। आम किसानों और साधारण जनता के रुख से लगता नहीं है कि यह बंद सफल हो पाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया है कि शुक्रवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक क्या बंद रहेगा और क्या नहीं? ऐसे में लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि क्या किसान आंदोलन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है? इसकी सच्चाई जाननी है कि आपको सिंघु के साथ-साथ टीकरी और यूपी बॉर्डर पर भी जाना होगा, जहां पर मुट्ठी पर किसान आंदोलनकारी रह गए हैं।

पंजाब लौटने को तैयार ट्रैक्टर ट्रॉली

जागरण संवाददाता के मुताबिक, दिल्ली-हरियाणा के सिंघु बॉर्डर पर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रदर्शनकारियों के लिए हाल ही में लगाया गया बड़ा टेंट लोगों की संख्या कम होने की वजह से खाली पड़ा है। सैकड़ों लोग जिसमें आराम से रह सकते हैं वहां आठ-दस लोग ही बैठे हुए हैं। टेंट में कार व ट्रैक्टर खड़े कर जगह भरने की कोशिश की जा रही है। उधर सिंघु बॉर्डर-नरेला रोड पर खड़े कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली वापस घर लौटने को तैयार हैं।

दिल्ली में गेहूं की फसल कटनी शुरू हो गई है। पंजाब में भी कुछ दिनों में फसल पकने लगेगी। सिंघु बॉर्डर पर बैठे प्रदर्शनकारियों में जिसे वास्तव में अपने खेतों की चिंता होगी, वह जरूर अपनी फसल की कटाई करने जाएंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में इनकी संख्या और भी घट सकती है। इन दिनों में खेतों में ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। इसलिए कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर भी इस दौरान वापस पंजाब जा सकते हैं।

वहीं, दिल्ली-यूपी सीमा पर गाजीपुर बॉर्डर पर तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में यूपी गेट पर धरना जारी है। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने 26 मार्च को भारत बंद का भी एलान किया है। प्रदर्शनकारियों की ओर से कहा गया है कि यूपी गेट की सभी लेनों को सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक बंद किया गया है।

नई दिल्ली में 25 से 21 साल की कानूनी पीने की उम्र कम करने वाली नई आबकारी नीति के बारे में एलजी अनिल बैजल के साथ बैठक के बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, रामवीर सिंह बिधूड़ी अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ ।

अपना वजूद बचाने में जुटे पंजाब के ये दो किसान, राकेश टिकैत ने भी बनाई दूरी

नई दिल्ली । सिंघु बॉर्डर पर समर्थकों के साथ बैठे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी (पंजाब) के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू व महासचिव सरवन सिंह पंधेर वजूद बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में तो कोई उनकी कमेटी को गंभीरता से नहीं ही ले रहा है, सिंघु बॉर्डर पर भी उनको अहमियत नहीं मिल रही है। कोई भी बड़ा पंजाबी अभिनेता या गायक कमेटी के मंच पर नहीं आता, सभी संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से ही लौट जाते हैं। राकेश टिकैत जैसे नेता भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के मंच पर अब तक नहीं आए हैं।

दरअसल, शहीदी दिवस पर मंगलवार को सिंघु बॉर्डर पर चल रहे संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर गायक रविंद्र ग्रेवाल पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों का मनोरंजन किया, लेकिन वह करीब 200 मीटर दूर दिल्ली की सीमा में लगाए गए कमेटी के मंच पर नहीं पहुंचे। इसका विरोध कमेटी के मंच से किसान नेताओं ने किया। उन्होंने कहा कि गायकों को इस मंच पर भी आना चाहिए।

सच्चाई यही है कि 26 जनवरी को लाल किले पर हुए उपद्रव के बाद से किसान मजदूर संघर्ष कमेटी से सभी ने कन्नी काट ली है। इस समय जब सभी नेता शांत नजर आ रहे हैं, सरवन सिंह पंधेर अपना वजूद बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वह कभी मंच से विवादित बयान देते हैं तो कभी मरने-मारने की बात करते हैं। उनकी मौजूदगी में खालिस्तान के समर्थन में नारे लगते हैं।

दीप सिद्धू व लक्खा सिधाना के साथ सतनाम पन्नू व सरवन सिंह पंधेर को भी गणतंत्र दिवस पर हुए उपद्रव का जिम्मेदार ठहराया गया है। सरवन सिंह पंधेर ने ही प्रदर्शनकारियों को लाल किले में जाने को कहा था। 25 जनवरी की रात को गैंगस्टर लक्खा सिधाना ने कमेटी के मंच से प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया था तो दीप सिद्धू ने संयुक्त किसान मोर्चा के मंच से पंधेर व पन्नू का साथ देने की अपील की थी। दीप सिद्धू ने तो देर रात को तिरंगे पर भरोसा न होने की बात तक कही थी।

संपादकीय

गर पता होता लॉकडाउन का हश्र

आयकर और प्रत्यक्ष कर की वसूली सरकार की उम्मीद से बेहतर हो गई है। फरवरी में लगातार तीसरे महीने जीएसटी की वसूली भी 1.10 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रही। डीजल की बिक्री कोरोना काल से पहले के स्तर पर पहुंच चुकी है और एक के बाद एक अंतरराष्ट्रीय एजेंसी भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा रही है। लेकिन इन खुशखबरियों के साथ ही कुछ परेशान करने वाली खबरें भी आ रही हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पिछले तीन महीनों में सबसे ऊपर आ गया है, तो थोक महंगाई का आंकड़ा 27 महीने की नई ऊंचाई पर है। अभी ये दोनों ही आंकड़े रिजर्व बैंक की चिंता का कारण नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने खतरे का निशान पार नहीं किया है। लेकिन डर है कि जल्द ही ऐसा हो सकता है, क्योंकि तेल का दाम बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ कच्चा तेल, बल्कि खाने का तेल और विदेश से आने वाली दालें भी महंगी हो रही हैं।

और यह सब तब, जब देश की आधी से ज्यादा आबादी लॉकडाउन के असर से निकलने की कोशिश में ही है। बहुत बड़ी आबादी के लिए यह कोशिश कामयाब होती नहीं दिख रही है। सरकार ने अगस्त में पीएफ दफ्तर के आंकड़े दिखाए थे और कहा था कि 6.55 लाख नए लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन पिछले सोमवार को श्रम मंत्री ने संसद में बताया कि गए साल अप्रैल से दिसंबर के बीच 71 लाख से ज्यादा पीएफ खाते बंद हुए हैं। यही नहीं, 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसी दौरान अपने पीएफ खाते से आंशिक रकम निकाली। रोजगार का हाल जानने के लिए कोई पक्का तरीका है नहीं, इसीलिए सरकार ने अब इस काम के लिए पांच तरह के सर्वे करने का फैसला किया है। इस तरह के सर्वेक्षण की जरूरत शायद नहीं पड़ती, अगर कोरोना का संकट न आया होता और पूरे भारत में लॉकडाउन का एलान न हुआ होता। दुनिया की सबसे बड़ी तालाबंदी करते वक्त अगर सरकारों को अंदाजा होता कि इसका क्या असर होने जा रहा है, तो शायद वे कुछ और फैसला करतीं। लेकिन अब पीछे जाकर फैसला तो पलटा नहीं जा सकता। जो होना था, हो चुका है।

लॉकडाउन का अर्थ था, देश की सारी आर्थिक गतिविधियों पर अचानक ब्रेक लगना। उसी का असर था कि अगले तीन महीने में अर्थव्यवस्था में करीब 24 प्रतिशत की गिरावट और उसके बाद की तिमाही में फिर 7.5 फीसदी की गिरावट के साथ भारत बहुत लंबे समय के बाद मंदी की चपेट में आ गया। अच्छी बात यह रही कि साल की तीसरी तिमाही में ही गिरावट थम गई, और तब से अब तक जश्न का माहौल बनाने की तमाम कोशिशें चल रही हैं। लेकिन किस्सा यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ ऐसे आंकड़े अब आ रहे हैं, जिनको पढ़कर फिर याद आने लगी है वे डरावनी खबरें, जो लॉकडाउन की शुरुआत में आ रही थीं। लाखों लोग बड़े शहरों को छोड़कर निकल पड़े थे। सरकारों के रोकने के बावजूद, पुलिस के डंडों से बेखौफ, सरकार की ट्रेनें और बसें बंद होने से भी बेफिक्र। यही वक्त था, जिसके बारे में बाद में सीएमआईई ने बताया कि सिर्फ अप्रैल महीने में भारत में 12 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई थी। हालांकि, कुछ ही महीनों में इनमें से करीब 11 करोड़ लोगों को कोई न कोई दूसरा काम मिल गया, पर पढ़े-लिखे नौकरीपेशा लोगों पर खतरा बढ़ा और उनकी नौकरियां बड़े पैमाने पर जाने लगीं। जिनकी बचीं, वहां भी तनख्वाहें खासा कम हो गईं। तब सीएमआईई के एमडी ने कहा कि यह लंबे दौर के लिए खतरनाक संकेत है। आज अपने आसपास देखिए, तो समझ में आता है कि वह किस खतरे की बात कर रहे थे। बैंकों ने रिजर्व बैंक को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि वर्किंग कैपिटल के लिए कर्ज पर ब्याज चुकाने से मार्च के अंत तक जो छूट दी गई थी, उसका समय बढ़ा दिया जाए। साफ है, बैंकों को डर है कि उनके ग्राहक अभी कर्ज चुकाने की हालत में नहीं आए हैं और दबाव डाला गया, तो कर्ज एनपीए हो सकते हैं। भारत सरकार के खुद के आंकड़े दिखा रहे हैं कि रिटेल, यानी छोटे लोन के कारोबार में निजी बैंक सबसे ज्यादा दबाव महसूस कर रहे हैं। इन्होंने इस श्रेणी में जितने कर्ज बांट रखे हैं, उनमें किस्त न भरने वाले ग्राहकों की गिनती 50 फीसदी से 380 फीसदी तक बढ़ चुकी है, मार्च से दिसंबर के बीच। इससे भी खतरनाक नजारा है उच्च शिक्षा के लिए दिए गए कर्जों का। सरकारी बैंकों ने 31 दिसंबर को 10 प्रतिशत से ज्यादा ऐसे कर्जों को एनपीए, यानी डूबने वाला कर्ज मान लिया है। इस साल होम लोन, कार लोन या रिटेल लोन के मुकाबले सबसे खराब हाल एजुकेशन लोन का ही है। कॉलेजों का हाल देख लीजिए या नई नौकरियों का, इनमें जल्दी सुधार के हालात भी नहीं दिखते। इस हाहाकार के बीच आपने यह खबर जरूर देखी होगी कि पिछले साल भारत में 55 नए अरबपति पैदा हो गए। लेकिन इसके साथ यह भी जानना जरूरी है कि इस साल देश में मध्यम वर्ग की आबादी में 3.25 करोड़ लोगों की गिरावट आई है।

इसमें रोजाना 10 से 50 डॉलर तक कमाने वाले लोग शामिल हैं। कम कमाई करने वालों, यानी रोज दो से सात डॉलर तक कमाने वालों की गिनती में भी 3.5 करोड़ की गिरावट आई है। अभी किसी का हाल बेहतर नहीं है, क्योंकि कुछ बेहद अमीर लोगों को छोड़ दें, तो अमीरों की सूची भी थोड़ी छोटी ही हुई है। और यही फिक्र की बात है कि देश में गरीबों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, इसमें 7.5 करोड़ नए लोग जुड़ गए हैं।यह अपने आप में एक बेहद गंभीर आर्थिक संकट का इशारा है। फिर जिस अंदाज में देश के अलग-अलग हिस्सों में कोरोना के नए मामले आ रहे हैं, उससे आशंका यह खड़ी हो रही है कि किसी तरह पटरी पर लौटती आर्थिक गतिविधि को कहीं एक और बड़ा झटका तो नहीं लग जाएगा। लॉकडाउन की पहली बरसी पर हम सबको यही मनाना चाहिए कि लोग दो गज की दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन और टीके का सहारा लेकर किसी तरह इस हाल से आगे निकलने का रास्ता बनाएं। वरना बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है।

प्रवीण कुमार सिंह

यूपीएससी उम्मीदवारों को सिविल सेवा की परीक्षा में मिले अतिरिक्त अवसर

अतिरिक्त प्रयास की मांग करने वाले सिविल सेवा उम्मीदवारों में बहुत छात्र ऐसे हैं जो इस परीक्षा में साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा कई बार दे चुके हैं। ऐसे में उन्हें कोरोना की वजह से सिविल सेवा परीक्षा कैरियर को छोड़ना पड़े तो यह उनके जीवन भर के लिए कसक रह जाएगी और भारतीय नौकरशाही भी इन प्रतिभाओं से वंचित रह जाएगी। यहां एक बात का जिक्र करना जरूरी है कि कोविड के कारण वर्ष 2020 में आयोजित सभी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की उपस्थिति बेहद कम रही है। ऐसे में केंद्र सरकार का दायित्व है कि कोरोना महामारी से प्रभावित यूपीएससी छात्रों को वर्ष 2021 की परीक्षा में बैठने का अतिरिक्त मौका दिया जाए। अन्यथा यूपीएससी छात्रों की कई वर्षों की मेहनत बेकार हो जाएगी।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा को देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा के तौर पर माना जाता है। भारत सरकार के अधीन आइएएस और आइपीएस सहित करीब 24 ऐसी सेवाएं हैं, जिनमें हर साल यूपीएससी द्वारा कराई जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के जरिये नियुक्तियां होती हैं। हर वर्ष लाखों युवा इस परीक्षा में शामिल होते हैं। यह परीक्षा तीन चरणों में पूरे साल भर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन कोरोना महामारी ने इस परीक्षा की तैयारी करने वाले लाखों अभ्यर्थियों पर गंभीर असर डाला। इस परीक्षा की तैयारी के लिए अध्ययन सामग्री व कोचिंग क्लास की जरूरत होती है।

लेकिन महामारी जनित कारणों से यह समुचित रूप से संभव नहीं हो सका। साथ ही, कोरोना महामारी के कारण अक्टूबर, 2020 में हुई सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कई उम्मीदवार शामिल नहीं हो पाए। कई छात्र ऐसे भी रहे, जो संक्रमण की वजह से तैयारी समुचित तरीके से नहीं कर सके। ऐसे में महामारी के दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए सभी के पास 2020 में परीक्षा छोड़ने से बचने का एक विकल्प होना चाहिए था, मगर यूपीएससी द्वारा अंतिम प्रयास में परीक्षा में बैठने वालों के लिए कोई विकल्प नहीं दिया गया और उन्हें पर्याप्त तैयारी के बिना ही परीक्षा में बैठना पड़ा। जिस वजह से परीक्षा में अपनी ओर से श्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाए। कोरोना के कारण प्रभावित सिविल सेवा अभ्यर्थियों को 2021 में एक अतिरिक्त मौका देने के संबंध में पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि यूपीएससी में अतिरिक्त प्रयास देना या न देना एक नीतिगत मसला है जिसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। यानी न्यायालय ने यूपीएससी

उम्मीदवारों की मांग को केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। सनद रहे कि केंद्र सरकार ने यूपीएससी के उम्मीदवारों को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान एक अतिरिक्त मौका देने के लिए पांच फरवरी 2021 को सहमति जाहिर की थी, लेकिन यह भी कहा कि जिन्होंने 2020 की परीक्षा में अपने सभी अवसरों को समाप्त कर दिया था, उनमें से जो उम्मीदवार आयु सीमा के भीतर हैं, केवल उन्हें ही अतिरिक्त मौका दिया जा सकता है। लेकिन यूपीएससी द्वारा निकाले गए चार मार्च के नोटिफिकेशन में आयु सीमा के भीतर वाले अभ्यर्थियों को भी अतिरिक्त मौका नहीं दिया गया है। इस कारण यूपीएससी उम्मीदवारों में रोष है। अहम सवाल यह है कि महामारी से प्रभावित होने की वजह से जो उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा नहीं दे पाए थे, उनको एक और अतिरिक्त अवसर क्यों नहीं दिया जा सकता है। जबकि इस तरह की छूट को पहले भी बढ़ाया जाता रहा है। वर्ष 1992 में अतिरिक्त मौका दिया गया था, जबकि 2015 में आयु पर छूट दी गई। महामारी की स्थिति असाधारण थी और सिविल सेवा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों में कई उम्मीदवार आवश्यक सेवाओं में सेवारत थे। ऐसे में सिविल सेवा परीक्षा में एक बार के लिए छूट देने पर विचार होना चाहिए।

यहां यह बताना जरूरी है कि यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के नोटिफिकेशन के मुताबिक, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 32 वर्ष की आयु तक सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने के लिए छह अवसर मिलते हैं, जबकि ओबीसी उम्मीदवारों को 35 वर्ष की आयु तक नौ अवसर मिलते हैं। एससी-एसटी के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष निर्धारित है, जबकि अवसर की कोई बाध्यता नहीं है। कोरोना की वजह से ही वर्ष 2021 में आइआइटी-जेईई तथा यूजीसी की नेट-जेआरएफ की परीक्षा में छात्रों को रियायत दी गई है तो यूपीएससी में क्यों नहीं दी जा सकती? इसी तरह का मौका ओडिशा राज्य सरकार ने भी पीसीएस छात्रों को दिया है। ऐसे में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों को अतिरिक्त मौका न देना भेदभाव पूर्ण और अतार्किक होने के साथ संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का उल्लंघन है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। यूपीएससी परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने को लेकर सितंबर 2020 में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने उस समय परीक्षा की तारीख को यथावत रखते हुए केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया था कि वे उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने पर विचार करें, जिनका अन्यथा ऊपरी आयु-सीमा के इसी विस्तार के साथ 2020 में अंतिम प्रयास है।

अनुमान है कि कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया में 73 प्रतिशत युवाओं की पढ़ाई में बाधा आई है। भारत में चूंकि शिक्षा की उपलब्धता के मामले में अलग अलग समुदायों के बीच भयंकर असमानता है, तो यहां पर युवाओं की शिक्षा में सबसे अधिक खलल पड़ता दिखा है, यूपीएससी के अभ्यर्थी भी इससे अछूते नहीं रहे। हां, यह बात सच है कि कोरोना काल में डिजिटल पढ़ाई एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभर कर सामने आया और वर्चुअल क्लास रूम को लेकर खासी चर्चा हो रही है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में एक बड़े तबके के पास न तो स्मार्टफोन है, न ही कंप्यूटर और न ही इंटरनेट की सुविधा। जाहिर है, ऐसे में ऑफलाइन क्लास बंद होने के कारण स्कूली तथा प्रतियोगी छात्रों को तैयारी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। यहां तक कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक समाचार-पत्रों की पहुंच भी सुनिश्चित नहीं हो पाई थी।

पिछले वर्ष जुलाई-अगस्त तक देश भर में कोरोना के मामलों की संख्या में लगातार इजाफा होने की वजह से कई परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी नहीं किया जा सका। इसके बाद दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को भी रद कर दिया था। यही नहीं, महामारी के प्रकोप के चलते विश्वविद्यालयों में शोध-अनुसंधान कार्य बंद था। इस दौरान छात्रों के व्यक्तित्व के समग्र विकास हेतु चलने वाली खेल, सांस्कृतिक गतिविधियां, कला संबंधी कार्यक्रम आदि भी रुके रहे। ऐसे में सरकार को समझने की जरूरत है कि कोरोना महामारी का असर सिर्फ स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि इसका प्रभाव जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों पर पड़ा है। कई क्षेत्रों के लिए सरकार ने रियायत भी प्रदान की है तो फिर यूपीएससी अभ्यर्थियों को भी रियायत मिलनी चाहिए। अतिरिक्त प्रयास की मांग करने वाले सिविल सेवा उम्मीदवारों में बहुत छात्र ऐसे हैं जो इस परीक्षा में साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा कई बार दे चुके हैं। ऐसे में उन्हें कोरोना की वजह से सिविल सेवा परीक्षा कैरियर को छोड़ना पड़े तो यह उनके जीवन भर के लिए कसक रह जाएगी और भारतीय नौकरशाही भी इन प्रतिभाओं से वंचित रह जाएगी। यहां एक बात का जिक्र करना जरूरी है कि कोविड के कारण वर्ष 2020 में आयोजित सभी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की उपस्थिति बेहद कम रही है। ऐसे में केंद्र सरकार का दायित्व है कि कोरोना महामारी से प्रभावित यूपीएससी छात्रों को वर्ष 2021 की परीक्षा में बैठने का अतिरिक्त मौका दिया जाए। अन्यथा यूपीएससी छात्रों की कई वर्षों की मेहनत बेकार हो जाएगी।

भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए चुनौतियों को दूर करने हेतु उठाने होंगे कदम

इस समय भारत के वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग का नया हब बनने की संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं। इसके पांच कारण हैं। एक, उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजना। दो, नई श्रम संहिताएं। तीन, उद्योग-कारोबार के नियमों का सरलीकरण। चार, क्वाड के कारण अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ कारोबारी संभावनाएं। पांच, कोरोना संकट के चलते चीन के प्रति नकारात्मकता के कारण भारत को वैश्विक औद्योगिक समर्थन। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार संवर्धन विभाग और नीति आयोग द्वारा पीएलआइ योजना पर आयोजित परिचर्चा में कहा कि इस योजना से अगले पांच वर्षों में देश में 520 अरब डॉलर यानी लगभग 40 लाख करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन होगा। इससे विदेशी निवेश बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेंगे और रोजगार के भी दोगुना होने की उम्मीद है।

गौरतलब है कि सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रोत्साहन एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए 24 सेक्टरों की पहचान की है। इनमें से अब तक 12 सेक्टरों को पीएलआइ स्कीम से जोड़ा जा चुका है। पिछले वर्ष मार्च 2020 में सबसे पहले पीएलआइ स्कीम के तहत सरकार के द्वारा मोबाइल विनिर्माण और विशेषीकृत इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, फार्मा ड्रग्स एवं एपीआइ एवं चिकित्सा उपकरणों जैसे क्षेत्रों के लिए 51,311 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन दिए गए हैं। फिर 11 नवंबर को पीएलआइ योजना के तहत 10 और सेक्टरों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपये के इंसेंटिव दिए गए। पीएलआइ योजना के तहत करीब दो लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पांच साल के लिए सुनिश्चित किए गए हैं।

केंद्र सरकार उद्योग-कारोबार को गतिशील करने के लिए विभिन्न 44 श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में तब्दील करने की महत्वाकांक्षी योजना को आकार देने में भी सफल रही है। सरकार ने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और वेतन संहिता कोड 2019 के तहत जहां एक ओर मजदूरी सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने का दायरा काफी बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर श्रम कानूनों की सख्ती कम करने और अनुपालन की जरूरतों को कम करने जैसी व्यवस्थाओं से उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेंगे।

सरकार उद्योग-कारोबार की जटिलताएं कम करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक सरकार 2021 में केंद्र और राज्य स्तर के 6,000 से अधिक कारोबारी नियमों को कम किए जाने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, 2020 में भारत 190 देशों की सूची में 63वें स्थान पर पहुंच गया। 2019 में भारत इस सूची में 77वें स्थान पर था। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि क्वाड भारत के उद्योग-कारोबार के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्वाड बैठक में जो बाइडन ने भारत को वैक्सीन निर्माण का बड़ा केंद्र बनाने का एलान किया। इससे भारत के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने को बड़ा आधार मिलेगा।

यह भी महत्वपूर्ण है कि कोविड-19 के बीच चीन के प्रति वैश्विक नकारात्मकता और भारत के प्रति सकारात्मकता के कारण चीन से बाहर निकलते विनिर्माण, निवेश और निर्यात के मौके भारत की ओर आने की संभावना बढ़ गई है। यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कई आर्थिक मापदंडों पर भारत अभी भी चीन से आगे है। भारत दवा निर्माण, रसायन निर्माण और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में सबसे तेजी से उभरता हुआ देश भी है। भारतीय फार्मा उद्योग पूरी दुनिया में अहमियत रखता है। भारत अकेला ऐसा देश है, जिसके पास यूएसएफडीए मानकों के अनुरूप अमेरिका से बाहर सबसे अधिक संख्या में दवा बनाने के प्लांट हैं।

भारत के पास तकनीकी और पेशेवर प्रतिभाओं की भी कमी नहीं है। भारत के पास 35 साल से कम उम्र की दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है। मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन आरसी भार्गव के मुताबिक यदि उद्योग और सरकार साथ मिलकर काम करें तो भारत सस्ती लागत के विनिर्माण में चीन को पीछे छोड़ सकता है। भारत में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले कम लागत के उत्पाद बनाए जा सकेंगे और विनिर्माण उद्योग जितनी अधिक बिक्री करेंगे, उससे अर्थव्यवस्था में उतने ही अधिक रोजगार सृजित होंगे। यद्यपि सरकार भारत को चीन के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की डगर पर आगे बढ़ रही है, पर इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को पाने के लिए लागत घटाने का प्रयास करना होगा। यह ध्यान देना होगा कि भारत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तभी विकसित हो पाएगा, जब अन्य देशों के मुकाबले लागत कम होगी। चूंकि कई उत्पादों के निर्माण के लिए भारत अभी भी बहुत कुछ आयात पर निर्भर है, इसलिए कच्चे माल को देश में उत्पादित करने के ठोस प्रयास किए जाने होंगे।

स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए शोध एवं नवाचार पर फोकस किया जाना भी जरूरी होगा। इसके साथ-साथ कुछ अन्य ऐसे सुधारों की डगर पर भी आगे बढ़ना होगा, जिनसे कारखाने की जमीन, परिवहन और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली की लागत आदि को कम किया जा सके। टैक्स के साथ अन्य कानूनों की सरलता भी जरूरी होगी।

आपदा में अच्छा सिनेमा

लंबे इंतजार के बाद बीते सोमवार को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई तो माहौल में खुशी के साथ-साथ थोड़ी राहत और भावुकता भी पगी हुई थी। विजेताओं और उनके फैंस के बीच खुशी और चूक गए कलाकारों और उनके प्रशंसकों के बीच हल्की सी मायूसी ऐसे मौके पर हर बार देखने को मिलती है। इस बार खास बात यह रही कि इस पुरस्कार समारोह के आगे और पीछे दोनों तरफ कोरोना वायरस के खौफ का साया पसरा नजर आया। इन पुरस्कारों की घोषणा 3 मई 2020 को होनी थी लेकिन कोरोना के कहर को देखते हुए खामोशी से इसे एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। तय हुआ कि 2021 में मई के पहले सप्ताह में दोनों वर्षों के पुरस्कारों की घोषणा एक साथ कर दी जाएगी। मगर कोरोना के नए मामले काफी नीचे चले जाने के बाद दोबारा तेजी से बढ़ने लगे हैं। इसकी दूसरी लहर आधिकारिक तौर पर घोषित हो चुकी है।

ऐसे में आशंका यह थी कि कहीं कोरोना दोबारा बेकाबू न हो जाए और पुरस्कार टलते ही चले जाएं। ऐसे में मई का इंतजार किए बगैर इसी सोमवार को बिना किसी धूमधाम के पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। जो फैसला फिल्म प्रशंसकों के एक बड़े हिस्से को भावुकता की लहर से भिगो गया, वह था 2019 में रिलीज हुई फिल्म %छिछोरे% को बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड मिलना। यह सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म थी, जिनकी आत्महत्या की खबर ने पिछले साल न केवल सबको चौंका दिया था बल्कि परदे पर दिखने वाली सुनहरी जिंदगी के पीछे छिपी कलाकार की वास्तविक जिंदगी के दुखों, संघर्षों और तनावों को भी लाइमलाइट में ला दिया था। बेस्ट ऐक्टर का अवॉर्ड मनोज वाजपेयी (भोसले) और धनुष (असुरन) को मिलना एक बार फिर इन दोनों कलाकारों की अभिनय क्षमता पर मोहर लगाने जैसा रहा। मणिकर्णिका और पंगा के लिए बेस्ट ऐक्ट्रेस का पुरस्कार जीतकर कंगना रनौत ने एक बार फिर अपनी क्षमता सिद्ध की है। फैशन, क्वीन और तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के बाद यह उनका चौथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है।

बहरहाल, ये पुरस्कार ऐसे समय घोषित हुए हैं जब सिनेमा की हमारी दुनिया आमूल-चूल बदलाव के दौर से गुजर रही है। पिछले साल के ज्यादातर हिस्से में सिनेमा हॉल बंद रहे और लोग मनोरंजन के लिए ओटीटी प्लैटफॉर्म्स की ओर मुड़े। अब जब सिनेमा हॉल खुल गए हैं तब भी वे दर्शकों की पहले जैसी भीड़ नहीं खींच पा रहे। ओटीटी इस बीच एक सशक्त और टिकाऊ विकल्प के रूप में उभर चुका है और यह सिनेमा के विषय तथा कथ्य को भी प्रभावित कर रहा है। इसके संपूर्ण प्रभावों के आकलन में वक्त लगेगा, लेकिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ज्यादा समय तक पूरी तरह ओटीटी के लिए बनने वाली फिल्मों और सीरीज से आंखें मूंदे रहें, यह ठीक नहीं होगा। न एक कला के रूप में सिनेमा के विकास की दृष्टि से, न ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की सार्थकता के लिहाज से।

शहरों में जीवन की सुगमता का मूल्यांकन, सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी दिल्ली की परेशानी

शहरों के स्तर पर बात करें तो इस बार के इंडेक्स में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि दिल्ली इस इंडेक्स में 13वें स्थान पर है। हालांकि दिल्लीवासियों के लिए यह एक सांत्वना वाली बात रही कि नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक में 10 लाख से कम जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इन परिणामों के पीछे क्या सही, क्या गलत हुआ, यह समझने की दृष्टि से अलग-अलग श्रेणियों और आयामों को देखें तो आर्थिक क्षमता में दिल्ली दूसरे स्थान पर रही और इसकी उप-श्रेणी आर्थिक मौकों की उपलब्धता के मामलों में पूरे 100 में 100 नंबर प्राप्त करने के अलावा हर श्रेणी में दिल्ली का प्रदर्शन बुरा रहा।

केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी ने इसी माह ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स (ईओएलआइ) 2020 और नगर पालिका कार्य निष्पादन सूचकांक (एमपीआइ) वर्ष 2020 की अंतिम रैंकिंग को जारी किया है। वर्ष 2020 में आयोजित मूल्यांकन प्रक्रिया में 111 शहरों ने भाग लिया था। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में सूची के लिए शहरों का वर्गीकरण जनसंख्या के आधार पर करते हुए दो सूचियां बनाई गईं। पहली उन शहरों की जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है और दूसरी उनकी जिनकी दस लाख से कम है। मालूम हो कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बेंगलुरु सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहर के रूप में उभरा, इसके बाद पुणो, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयंबटूर, वडोदरा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई का स्थान रहा। कुल 49 शहर इसमें शामिल थे जिनमें से 42 ने 50 से ऊपर का स्कोर किया। दूसरे वर्ग यानी 10 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में शिमला सर्वोच्च स्थान पर रहा, इसके बाद भुवनेश्वर, सिलवासा, काकीनाडा, सलेम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, दावणगेरे और तिरुचिरापल्ली रहे। इस वर्ग में कुल 62 शहरों को शामिल किया गया था जिनमें से 48 ने 50 से अधिक का स्कोर किया।

ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और नगर निगम का प्रदर्शन सूचकांक -इस पूरी प्रक्रिया में जिन मानकों को आधार बनाया जाता है, उनका सीधा संबंध संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में अपनाए गए सस्टेनेबल

डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य और उन आयामों से जुड़ता है जो शहरी विकास से जुड़े हुए हैं और जिनके लिए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रलय जिम्मेदार है। दुनिया के स्तर पर देखें तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हर वर्ष इसी प्रकार की एक ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग प्रकाशित करती है, जिसमें यह आकलन किया जाता है कि दुनिया के कौन से शहर सवरेत्तम रहने की स्थिति प्रदान करते हैं। इस वैश्विक सर्वे में दुनिया के 140 शहरों में व्यक्तिगत जीवनशैली का आकलन किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक शहर में स्थिरता, स्वास्थ्य और पर्यावरण समेत शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े लगभग 30 कारकों की माप की जाती है।

केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रलय की इस पूरी प्रक्रिया में शहरी विकास के 13 विभिन्न पक्षों या सेवाओं का आकलन तीन पहलुओं को ध्यान में रख कर किया जाता है। पहला, उस शहर में जीवन की गुणवत्ता क्या है यानी उसमें सामान्य जीवन से जुड़ी सुविधाओं की स्थिति और उन सुविधाओं का वहां के नागरिकों पर प्रभाव कितना और कैसा है। इसके लिए इस इंडेक्स में कई मानक रखे गए हैं, मसलन शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, आश्रय, जलापूर्ति और इससे जुड़ी साफ-सफाई और स्वास्थ्य सुविधा, आवागमन की सुविधा तथा सड़कों एवं फुटपाथ की स्थिति, नागरिकों की सुरक्षा व मनोरंजन आदि।

इस बार के इंडेक्स में इसका भारांक 35 प्रतिशत की थी। दूसरा, शहरों की आर्थिक क्षमता, जिसके आकलन के लिए दो मानक रखे गए हैं। एक शहर का आर्थिक विकास और दूसरा शहर में उपलब्ध रोजगार के अवसर। इंडेक्स में इसका भारांक 15 प्रतिशत था। तीसरा पहलू था संवहनीयता (सस्टेनेबिलिटी) यानी पर्यावरण, ऊर्जा की खपत और लचीलापन। इसका भारांक 20 प्रतिशत था। शेष 30 प्रतिशत मूल्यांकन, सिटीजन पर्सेप्शन सर्वे के माध्यम से नगर प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के बारे में नागरिकों के दृष्टिकोण पर आधारित था। सीपीएस यानी सिटीजन पर्सेप्शन सर्वे को सेवा की आपूर्ति के संदर्भ में अपने शहर के नागरिकों के अनुभव को मान्यता देने में मदद के लिए शुरू किया गया था। यह मूल्यांकन 16 जनवरी से 20 मार्च 2020 तक किया गया था। इस सर्वेक्षण में 111 शहरों के 32.2 लाख नागरिकों ने भाग लिया। भुवनेश्वर का सीपीएस स्कोर सबसे अधिक था, उसके बाद सिलवासा, दावणगेरे, काकीनाडा, बिलासपुर और भागलपुर का स्थान रहा। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स सूचकांक के एक परिणाम को मापता है, जबकि नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक उन घटकों पर ध्यान केंद्रित करता है जो उन परिणामों को पैदा करते हैं। नगर पालिका कार्य प्रदर्शन उन तत्वों की पहचान करने का काम करता है जो सेवा वितरण तंत्र, योजना, वित्तीय प्रणालियों और शासन प्रक्रिया में कुशल स्थानीय शासन को रोकते हैं। नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक भारतीय नगर पालिकाओं की उनके निर्धारित कार्यो में कार्य प्रदर्शन का आकलन और विश्लेषण करने का एक प्रयास है। एक नगर पालिका की जिम्मेदारियां वर्टिकल सीरीज में फैली होती हैं, जिनमें शहरी योजना जैसे जटिल मूलभूत जनसेवाओं का प्रविधान भी शामिल है। नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक नगर पालिकाओं की कार्यक्षमता और उनकी विकास क्षमताओं की सीमा के बारे में सक्षम जानकारी प्रदान करता है। सूचकांक के माध्यम से, नागरिक अपने स्थानीय सरकार के प्रशासन को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, जो पारदर्शिता का निर्माण करता है और प्रमुख हितधारकों में विश्वास पैदा करता है। इस ढांचे में शामिल 20 विभिन्न क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और अपशिष्ट जल और स्वच्छता, पंजीकरण और परमिट, बुनियादी ढांचा, राजस्व प्रबंधन, व्यय प्रबंधन, राजकोषीय विकेंद्रीकरण, डिजिटल प्रशासन, डिजिटल पहुंच, डिजिटल साक्षरता, योजना तैयार करना, योजना लागू करना, योजना प्रवर्तन, पारदर्शिता और जवाबदेही, मानव संसाधन, भागीदारी और प्रभावशीलता हैं। शहरों में बुनियादी सुविधाओं के आकलन के अतिरिक्त इस पूरी प्रक्रिया के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। पहला तो शहरों के बीच एक दूसरे से बेहतर करने के लिए और दूसरा शहरों का खुद के पिछले साल के स्कोर में बढ़ोतरी करने को प्रोत्साहित करना जिससे नागरिकों और जिम्मेदार संस्थाओं दोनों का ध्यानाकर्षण हो और बेहतरी की एक मिली-जुली कोशिश होती रहे। इस दृष्टि से क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो दक्षिण भारत के शहरों का प्रदर्शन अन्य क्षेत्रों के शहरों की तुलना में अधिक सही रहा। दोनों ही वर्गो के 10 लाख से ऊपर या कम आबादी में डिंडीगुल को छोड़ दिया जाए तो दक्षिण भारत के किसी भी शहर का स्कोर 50 से कम नहीं रहा। सबसे बुरी स्थिति पूर्वी भारत की रही जहां सिर्फ तीन शहरों ने ही 50 से ऊपर का स्कोर किया। शहरों के स्तर पर बात करें तो इस बार के इंडेक्स में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि दिल्ली इस इंडेक्स में 13वें स्थान पर है। हालांकि दिल्लीवासियों के लिए यह एक सांत्वना वाली बात रही कि नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक में 10 लाख से कम जनसंख्या वाली नगर पालिकाओं में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इन परिणामों के पीछे क्या सही, क्या गलत हुआ, यह समझने की दृष्टि से अलग-अलग श्रेणियों और आयामों को देखें तो आर्थिक क्षमता में दिल्ली दूसरे स्थान पर रही और इसकी उप-श्रेणी आर्थिक मौकों की उपलब्धता के मामलों में पूरे 100 में 100 नंबर प्राप्त करने के अलावा हर श्रेणी में दिल्ली का प्रदर्शन बुरा रहा।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91 से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का चुनाव 20 को, हाईकोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को झटका

लखनऊ । शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में प्रशासक नियुक्त करने के मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का उत्तर प्रदेश सरकार के इस मामले में जवाब-तलब किया है। इस केस में गुरुवार को सुनवाई को देखते हुए सरकार ने 20 अप्रैल को चुनाव कराने का फैसला किया है।

उत्तर प्रदेश में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का चुनाव 20 अप्रैल को होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ की फटकार के बाद बुधवार देर रात को प्रदेश सरकार ने शिया वक्फ बोर्ड के प्रशासक पद से प्रमुख सचिव

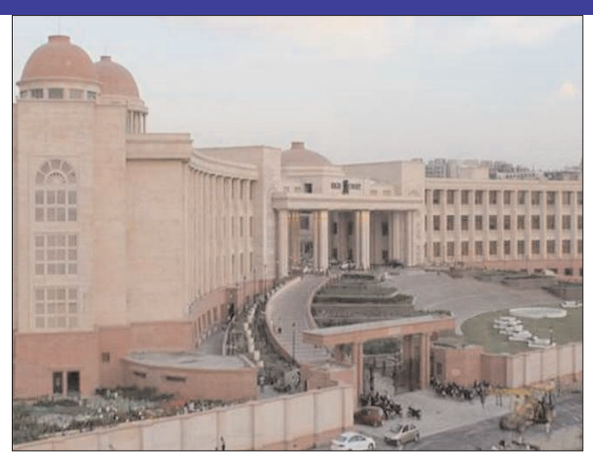

अल्पसंख्यक कल्याण बीएल मीणा को हटा दिया है। हाईकोर्ट ने कहा था कि शिया वक्फ बोर्ड में प्रशासक किस नियम के तहत तैनात किए गए हैं।

हाईकोर्ट में गुरुवार को इस मामले की सुनवाई होनी है। इसी कारण सरकार ने प्रशासक नियुक्ति का फैसला वापस ले लिया है। इसके साथ ही अफसर देर रात तक चुनाव कार्यक्रम तैयार करने में जुटे रहे। सूत्रों का कहना है कि सरकार कोर्ट में चुनाव कार्यक्रम पेश करेगी। शिया वक्फ बोर्ड के चुनाव 20 अप्रैल को होने की उम्मीद है।

शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से अध्यक्ष पद पर चुनाव होना था, लेकिन अभी तक नहीं कराया गया है। पिछले दिनों सरकार ने शिया वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला ले लिया। सरकार ने प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण बीएल मीणा को उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में प्रशासक नियुक्त कर दिया। सरकार के इसी फैसले को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है।

इस पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को हाईकोर्ट ने पूछा कि किस प्रावधान के तहत शिया वक्फ बोर्ड में प्रशासक की नियुक्ति की गई है. साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि बोर्ड में जल्द से जल्द चुनाव करा लिए जाएं।

हाईकोर्ट ने मामले में वक्फ और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव स्तर के अफसर से 25 मार्च को कोर्ट में की गई कार्यवाही से अवगत कराने का आदेश दिया है। दरअसल सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण चुनाव कराने में असमर्थता जताते हुए शिया वक्फ बोर्ड में प्रशासक नियुक्त कर दिए थे। इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि किस आधार पर प्रशासक नियुक्त किया गया है।

डीएपी के रेट बढ़ने पर अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर जोरदार हमला, बोले- किसानों पर महंगाई की मार

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों किसानों के प्रदर्शन का भी जोरदार समर्थन कर रहे हैं। डीएपी के रेट बढ़ने से अखिलेश यादव के विरोध को ऑक्सीजन मिली है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव डीएपी की कीमत बढ़ने से काफी भड़के हैं। इसको लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, किसानों पर महंगाई की मार, शर्म करे भाजपा सरकार।

अखिलेश यादव ने डीएपी के दाम बढ़ाने को लेकर केंद्र के साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह किसानों पर दोहरी मार है। पहले तीन कृषि कानून लागू किया गया, अब डीएपी के दाम को बढ़ाया गया है। किसान पहले से ही फसल का उचित दाम न मिलने के कारण परेशान हैं, लेकिन अब उनकी परेशानी और बढ़ चुकी है। भाजपा सरकार ने डीएपी के दाम में 300 रुपये तक की वृद्धि कर दी है। सपा प्रमुख ने कहा है कि भाजपा सरकार किसानों पर लगातार हो रहे अत्याचार बंद कर, सभी बढ़े हुए दामों को वापस ले।

निजी कंपनियों ने 50 किग्रा के बैग की कीमत 300 रुपये बढ़ा दी है। अभी तक उत्तर प्रदेश में डीएपी के 50 किग्रा के एक बैग की कीमत 1200 रुपये थे, लेकिन निजी क्षेत्र पीपीएल व जीएसएफसी ने इसका प्रिंट रेट 1500 रुपये कर दिया है।

संक्षिप्त खबर

मुजफ्फरनगर पहुंचे महाराष्ट्र व गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, कार्यक्रम को लेकर शहर में नाकाबंदी

मुजफ्फरनगर । उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी आज खतौली पहुंच गए। यहां पर इनका हेलीकाप्टर करीब 11.15 मिनट पर उतरा। यहां पर इनके कई कार्यक्रम हैं, जिसे लेकर खतौली में नाकाबंदी की गई है। साथ ही जानसठ रोड के बाजार भी बंद है। सुरक्षा के लिए फोर्स भी तैनात की गई है। इसके अलावा पुलिस बल भी तैनात है।

महाराष्ट्र एवं गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी गुरुवार को कुंद-कुंद जैन कालेज में मेधावी तथा पुरातन छात्र-छात्राओं को सम्मानित करेंगे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कालेज के क्रीड़ा मैदान स्थित हेलीपैड पर सुबह 11:15 बजे हेलीकाप्टर से पहुंच गए। कार द्वारा कालेज परिसर में पहुंचकर नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इसके बाद सभागार में मेधावी, पुरातन छात्र-छात्राओं को सम्मानित करेंगे। यहां से करीब 1:45 बजे वह शुगर मिल गेस्ट हाउस रवाना होंगे। बुधवार को एसपी सिटी अर्पित विजय वर्गीय, एसपी देहात दुर्गेश विजय सिंह, सीओ आशीष प्रताप सिंह, सीओ शकील अहमद ने एलआइयू व इंस्पेक्टर के साथ महाविद्यालय के सभागार, भवन आदि में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।

कस्बे से नहीं गुजरेंगे वाहन- गुरुवार सुबह दस से शाम छह बजे तक कस्बे के अंदर रोडवेज बसों और अन्य बड़े वाहनों का संचालन नहीं होगा। सहायक यातायात निरीक्षक ने रूट डायवर्ट किया है। बसों को भैंसी, भंगेला बाईपास से निकाला जाएगा। रेलवे रोड, शिव मूर्ति पर फल एवं सब्जी बाजार को कार्यक्रम के दौरान बंद रखा जाएगा। जानसठ किराए से लेकर शुगर मिल गेट तक फोर्स का पहरा बिठाया गया है। नगर में भी भारी वाहनों के आवागमन पर शाम 4 बजे तक प्रतिबंध रहेगा।

पंजाब में कांग्रेस को महंगा पड़ सकता है राय सिख बोर्ड का गठन, नई दिक्कत पैदा होने की आशंका

चंडीगढ़ । पंजाब में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए पंजाब सरकार ने राय सिख बोर्ड का गठन कर दिया है। करमजीत सिंह तूतां को बोर्ड का चेयरमैन और मनोहर सिंह को उप चेयरमैन लगाया गया है। दोनों नेताओं ने पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ की उपस्थिति में बुधवार को अपना पदभार ग्रहण किया। उधर, राजनीतिक माहिरों का कहना है कि भले ही कांग्रेस ने यह कदम फिरोजपुर व फाजिल्का जिलों में राय सिखों की ज्यादा आबादी को देखते हुए लिया है लेकिन बोर्ड का गठन कांग्रेस के लिए नया संवैधानिक और सामाजिक संकट खड़ा कर सकता है। क्योंकि अनुसूचित जाति वर्ग की अन्य जातियां राय सिखों के लिए अलग से बोर्ड बनाने से निराश हैं। काबिलेगौर है कि मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने राय सिखों को 2007 में ओबीसी से निकालकर अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाया था, जिसके चलते पंजाब में अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या काफी ज्यादा हो गई। इस कारण राज्य में लोकसभा की आरक्षित सीटों की संख्या तीन से बढ़कर चार और विधानसभा की सीटों की संख्या 29 से बढ़कर 34 हो गई। राय सिख इस आरक्षण का लाभ तो लेते हैं लेकिन कहा यह भी जाता है कि वह अपने आप को अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित कहलाने से कतराते हैं। पैगाम संस्था के संयोजक और पूर्व आइएएस अधिकारी एसआर लद्दड़ का कहना है कि सरकार ने संवैधानिक उल्लंघन कर बोर्ड का गठन किया है। उन्होंने बताया कि संविधान के मुताबिक अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की मुश्किलों के लिए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग पहले से ही गठित है। ऐसे में राय सिख बोर्ड का कोई महत्व नहीं रह जाता। उन्होंने दलील दी कि अनुसूचित वर्ग की सूची में 29 जातियां दर्ज हैं। तो क्या अब पंजाब सरकार हर जाति के लिए अलग से बोर्ड गठित करेगी।

उन्होंने कहा कि एक वर्ग की वोटों के लिए गठित किया गया बोर्ड दूसरे वर्ग के लोगों में निराशा पैदा करता है। अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को 22.5 फीसद आरक्षण का लाभ दिया जाता है। आबादी के मुताबिक यह कोटा बढ़ाया जाना चाहिए था। संविधान बचाओ कमेटी के नेता करनैल सिंह जीत, कुलदीप चंद और नेशनल शेड्यूल कास्ट के प्रधान परमजीत सिंह कैंथ ने कहा कि कैप्टन सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राय सिख और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों में काफी विभिन्नता है। दलित वर्ग से संबंधित लोग भूमिहीन हैं जबकि राय सिख भाईचारे के पास काफी जमीन है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने बोर्ड के नवनियुक्त चेयरमैन और उप चेयरमैन को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार समाज के सभी भाईचारों को आदर करती है। सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं बनाकर लागू कर रही है।

मोहाली में भाजपा प्रवक्ता अनिल सरीन बोले- कैप्टन सबसे झूठा आदमी, विस चुनाव को लेकर किया ये एलान

मोहाली । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता अनिल सरीन ने वीरवार को मोहाली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला बोला। अनिल सरीन ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कई बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पंजाब में अगर सबसे झूठे आदमी का खिताब अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। भाजपा प्रवक्ता अनिल सरीन ने मोहाली में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कांग्रेस सरकार के चार साल के कामकाज पर सवाल खड़े करते हुए यह बात कही। सरीन ने कहा कि कैप्टन सरकार 85 फीसद वायदे पूरे करने का दावा कर रही है, लेकिन सच्चाई उलट है। नशे से लेकर किसानों के कर्जे माफी तक के किसी भी वायदे को कैप्टन सरकार ने पूरा नहीं किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करेगी। सवाल के जवाब में सरीन ने कहा कि पंजाब में बीते माह हुए नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत को वे नहीं मानते। क्योंकि ये जनता का फैसला नहीं है। कांग्रेस ने पूरे चुनाव में धक्केशाही कर भाजपा उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार नहीं करने दिया और भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन तक रद करवाए गए। उन्होंने कहा कि तीन कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डरों पर जो बैठे हैं वे किसान हैं या नहीं, इस बारे में सभी लोग बेहतर जानते हैं।

बसपा मुखिया मायावती का महिलाओं के प्रति अपराध पर यूपी सरकार पर निशाना

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी में लगीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। महिलाओं के प्रति लगातार बढ़ते अपराध पर चिंता जताने के साथ ही मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार पर लगातार बढ़ते मामलों पर रोक लगाने की सलाह दी है।

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री तथा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में इन दिनों बढ़ते अपराध पर चिंता जताई है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर मायावती ने गहरी चिंता जताने के साथ ही सरकार को सलाह भी दी है। इंटरनेट मीडिया पर बेहद एक्टिव हो चुकीं मायावती ने गुरुवार को इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को सलाह देने के साथ सरकार पर निशाना भी साधा है।

मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खासकर महिलाओं की असुरक्षा से सम्बन्धित जघन्य अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जो अति-दुःखद व चिन्ता की बात। उन्होंने कहा कि पीलीभीत व गोण्डा में बड़ी संख्या में महिलाओं असुरक्षा के साथ ही एटा में महिलाओं के साथ पुलिस की बर्बरता बेहद शर्मनाक है। इतना ही नहीं झांसी में ट्रेन से केरल की कई नन को को उतार देने का प्रकरण को बेहद ही शर्मनाक तथा घोर निन्दनीय है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इस प्रकार के बढ़ते मामलों की ओर तत्काल ध्यान दे। इस तरह के मामले और बढ़ने से स्थिति गंभीर भी हो सकती है। अब तो उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था में सुधार बेहद जरूरी है।

मथुरा के पास नंदगाँव में लोग लठमार होली मनाते हुए ।

तेजस्वी ऐसा बेटा, जिसने लालू को टॉयलेट में किया था बंद, भड़के कुशवाहा ने खोला बड़ा राज

पटना । बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को जनता दल यूनाइटेड के विधान पार्षद उपेंद्र कुशवाहा ने उनकी ही भाषा में जवाब दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ले तेजस्वी के अमर्यादित बोल पर कुशवाहा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि सुन लो तेजस्वी, जुबान पर लगाम लगाओ। उन्होंने एक बड़ा खुलासा यह भी किया कि तेजस्वी ने एक बार अपने पिता लालू प्रसाद यादव को शौचालय में बंद कर दिया था। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जाए।

तेजस्वी के अमर्यादित बोल पर बोले उपेंद्र कुशवाहा- विदित हो कि मंगलवार को बिहार विधानसभा में विपक्ष ने बड़ा बवाल किया। हंगामा व उत्पात इतना बढ़ा कि बाहर से पुलिस बुलाकर विपक्षी विधायकों को सदन से बाहर करना पड़ा था। इसके बाद से वार-पलटवार का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के लिए अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया। बुधवार को इसपर उपेंद्र कुशवाहा ने प्रतिक्रिया दी है।

बर्दाश्त के बाहर की भाषा, जुबान पर लगाओ लगाम- कुशवाहा ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पिता की उम्र के समतुल्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वे बर्दाश्त के बाहर हैं। तेजस्वी को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने लगभग आजीवन लालू के विरोध की ही राजनीति की है, लेकिन उनको ललूआ कहने वालों को मुंहतोड़ जबाव भी देते रहे हैं। तुमको भी मेरी सलाह है कि अपनी कब्र मत खोदो। जुबान पर लगाम रखो क्यों नौंवी फेल कहने वालों को खुद ही और मौका देते हो

कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज अगर लालू जेल से बाहर होते तो वे बेटों को समझाने की कोशिश करते, लेकिन बेटे उनकी बात कितनी मानते कह नहीं सकते हैं।

शायद बेटों से अपमानित होने से बेहतर वे चुप रहना ही समझते। तेजस्वी ने तो एक बार लालू प्रसाद यादव को शौचालय में बंद कर दिया था।

कुशवाहा ने आगे कहा कि लालू के बेटे आरजेडी में बड़े नेताओं का भी अपमान करते रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह व जगदानंद सिंह के उदाहरण समाने ही हैं। महागठबधन में रहते मेरा अपमान करने की हिम्मत जो वे नहीं कर सके, लेकिन आदत तो यही है। मुख्यमंत्री का अपमान बिहार की जनता का अपमान है। इस लिहाज से तो वे अब जनता का भी अपमान करने लगे हैं।

आगरा में शहीद दारोगा प्रशांत को पुलिस लाइन में अधिकारियों ने दी सलामी, पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार

आगरा । आगरा के खंदौली थाने में तैनात शहीद हुए दारोगा प्रशांत कुमार यादव पुलिस लाइन में एडीजी, आइजी प एसएसपी समेत अन्य अधिकारियों ने सलामी दी। इसके बाद स्वजन दारोगा के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए बुलंदशहर के पैतृक गांव लेकर रवाना हो गए। उनके साथ आगरा पुलिस भी गई है। खंदौली थाने में तैनात दारोगा प्रशांत कुमार यादव बुधवार शाम को नहर्रा गांव दो भाइयों के बीच झगड़े की सूचना पर गए थे। गांव में भाइयों शिवनाथ और विश्वनाथ के बीच आलू की फसल को लेकर विवाद हो गया था। शिवनाथ हाथ में तमंचा लेकर आलू की खोदाई करके ले जाने वाले मजदूरों को धमका रहा था। विवाद सुलझाने के लिए खेत पर पहुंचे दारोगा प्रशांत कुमार यादव ने विश्वनाथ के हाथ में तमंचा देखा। उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़े तो विश्वनाथ ने तमंचे से गोली मार दी। जो प्रशांत की गर्दन में लगी और उनकी मौत हो गई।

प्रशांत कुमार का पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार की सुबह करीब आठ बजे पुलिस लाइन पहुंचा। एडीजी राजीव कृष्ण, आइजी रेंज ए.सतीश गणेश, एसएसपी बबलू कुमार, डीएम प्रभु एन सिंह, एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद, एसपी ग्रामीण सत्यजीत गुप्ता समेत अन्य अधिकारियों ने दारोगा प्रशांत कुमार को सलामी दी। राज्यमंत्री डा. जीएस धर्मेश और विधायक रामप्रताप सिंह चौहान ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद स्वजन प्रशांत के पार्थिव शरीर को लेकर बुलंदशहर के पैतृक गांव छतारी लेकर रवाना हो गए।

दारोगा प्रशांत कुमार के स्वजन रात में ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खंदौली पर पहुंच गए थे। दारोगा का पार्थिव शरीर यहीं पर रखा गया था।स्वजन दारोगा के शव का पंचनामा भरने को राजी नहीं थे। उनका कहना था कि दारोगा को विवाद की सूचना पर फोर्स के साथ क्यों नहीं भेजा गया। अकेले ही एक पुलिसकर्मी के साथ भेज दिया गया। स्वजन का कहना था कि वह हत्यारोपित की गिरफ्तारी के बाद ही शव का पंचनामा भरेंगे।

तेजस्वी का सीएम नीतीश पर फिर नया हमला, बोले- आपके मुंह से अच्छी नहीं लगतीं मर्यादा की बातें

पटना । शुक्रवार 26 मार्च के किसानों के भारत बंद का राष्ट्रीय जनता दल ने समर्थन किया है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनका मुद्दा बेरोजगारी होगा। विधानसभा में मंगलवार को विपक्षी विधायकों के हंगामा तथा उन्हें पुलिस द्वारा जबरन निकाले जाने की घटना के बारे में तेजस्वी ने कहा कि अधिकारियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्लीनचिट दी है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री से पूछा कि क्या सदन में किसी बिल का विरोध पहली बार हुआ क्या विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष को पहली बार घेरा गया हां, यह पहली बार ऐसा जरूर हुआ है कि पुलिस के बल पुलिस बिल पास हुआ। विधायकों की पिटाई भी पहली बार हुई। तेजस्वी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुंह से मर्यादा की बातें अच्छी नहीं लगतीं।

तेजस्वी ने कहा कि आज से 46-47 साल पहले समाजवादियों ने आसन पर बैठकर हाउस चलाया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन किसी ने पुलिस को नहीं बुलाया था। कर्पूरी ठाकुर भी विधेयक लाए थे। विपक्ष के विरोध के बाद उन्होंने सेलेक्ट कमेटी में भेजा गया था।

1986 में नीतीश भी हाउस के सदस्य थे। कर्पूरी नेता प्रतिपक्ष थे। एचइसी को लेकर तीन दिन तीन रात तक विधानसभा में ही धरना दिया और सोये। नीतीश खुद भी सदस्य थे। कर्पूरी ठाकुर तीन दिन सदन के अंदर ही सोये। तब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन पुलिस को नहीं बुलाया गया।

पहले की लोकतंत्र की हत्या, अब कर रहे मर्यादा की बातें

तेजस्वी ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असत्य बोल रहे हैं। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। आज वे मर्यादा की बात कर रहे हैं। उन्हीं के मंत्री इसी विधानसभा के बजट सत्र में अंगुली दिखाकर बहस करते दिखे। तब तो उन्होंने मर्यादा की बात नहीं की। केवल आसन की तौहीन को देखते रहे।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव पटना में अपने आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ।

पुलिस से भिड़ी आरजेडी, पथराव व लाठीचार्ज के बीच दर्जनों घायल

पटना । बिहार विधानसभा के घेराव के लिए पटना के गांधी मैदान के पास स्थित जेपी गोलंबर से निकले राष्ट्रीय जनता दल के मार्च के दौरान पटना में जमकर उपद्रव हुआ है। कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रशासन की मनाही के बावजूद आरजेडी नेता व कार्यकर्ता काफी संख्या में जेपी गोलंबर के पास इकट्ठा होकर विधानसभा के लिए रवाना हो गए। उन्होंने जेपी गोलंबर के पास लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। इसके बाद डाकबंगला चौराहे पर उनकी पुलिस-प्रशासन से जबर्दस्त झड़प हुई, जिसमें दोनों ओर से कम से कम दो दर्जन लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। आरजेडी ने मीडिया पर भी हमला किया। जब वाटर कैनन से बात नहीं बनी तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने मार्च का नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को हिरासत में ले लिया।

बेरोजगारी और अपराध सहित कई मुद्दों पर आंदोलन- बेरोजगारी, अपराध, महंगाई एवं अशिक्षा के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी की ओर से मंगलवार को विधानसभा का घेराव किया जाना था। असम की चुनावी यात्रा से खासतौर पर इस आंदोलन के लिए तेजस्वी खुद पटना लौटे। युवा आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने दावा किया था कि घेराव कार्यक्रम में बड़ी तादाद में कार्यकर्ता एवं आम लोग शिरकत करेंगे। युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मो. कारी सोहैब के नेतृत्व में सारी तैयारी की गई। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने घेराव को इतिहास से जोड़ा। उन्होंने कहा कि महंगाई और तानाशाही के मुद्दे पर 18 मार्च 1974 को बिहार के छात्रों ने लालू प्रसाद के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया था। 47 वर्ष बाद तेजस्वी यादव के नेतृत्व में फिर वही आक्रोश है।

आरजेडी ने सरकार पर लगाया जनविरोधी होने का आरोप- आरजेडी ने सरकार पर जनविरोधी होने का आरोप लगाया है। आरजेडी के प्रदेश महासचिव विनोद यादव ने कहा है कि राजधानी के विभिन्न इलाकों में युवा आरजेडी द्वारा लगाए गए सैंकड़ों होर्डिंग-पोस्टर को नीतीश कुमार के इशारे पर नगर निगम प्रशासन ने हटा दिया है। सरकार की यह जनविरोधी नीति है। विधानसभा घेराव के ऐलान से सरकार डर गई है।

एक नजर

परमबीर सिंह का लेटर बम- गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे सरकार से मांगा जवाब

मुंबई । महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार से परमबीर सिंह के लेटर के मामले में जवाब मांगा है। गवर्नर ने महाराष्ट्र सरकार को लिखी चिट्ठी में पूछा है कि आखिर परमबीर सिंह की ओर से लगाए गए आरोपों को लेकर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। इस बीच आज शाम को महाविकास अघाड़ी के नेता भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर अपना पक्ष रख सकते हैं। बुधवार को ही बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार समेत कई नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और उद्धव ठाकरे सरकार से जुड़ी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजने की मांग की थी।

महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा कि वह गुरुवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगे और उनके समक्ष सरकार का पक्ष प्रस्तुत करेंगे। नाना पटोले के बयान के बाद राजभवन की तरफ से प्रतिक्रिया आई, जिसमें बताया गया कि कांग्रेस की ओर से कोई अपॉइंटमेंट नहीं लिया गया है। इसके साथ ही राजभवन ने बताया कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुंबई से बाहर हैं।

दुनियाभर की जेलों में बंद है 8 हजार भारतीय, सऊदी अरब में सबसे ज्यादा कैदी

नई दिल्ली । दुनियाभर के 82 देशों की अलग-अलग जेलों में लगभग 8 हजार भारतीय कैदी बंद है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय ने संसद में दी है। उनमें से, 4058 कैदी छह खाड़ी देशों में बंद हैं। इन देशों भारतीय पारंपरिक रूप से रोजगार के बेहतर अवसरों के लिए आते हैं। स्था के अनुसार, 267 भारतीय कैदी अमेरिका में और 373 यूके में बंद हैं। ग्यारह देशों की जेलों में 100 से अधिक भारतीय हैं। 1570 कैदियों के साथ सबसे अधिक अपराधी सऊदी अरब में बंद हैं। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात है, जिसमें 1292 भारतीय कैदी हैं। विदेश मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, कुवैत में 460 भारतीय, क़तर में 439, बहरीन में 178, ईरान में 70 और ओमान में 49 भारतीय बंदी हैं।

इसके अलावा अधिकतम नेपाल (886), उसके बाद पाकिस्तान (524), चीन (157), बांग्लादेश (123), भूटान (91), श्रीलंका (67) और म्यांमार (65) हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्था के अनुसार अफगानिस्तान में कोई भी भारतीय कैदी नहीं है। मलेशिया में 409 भारतीय कैदी हैं, सिंगापुर में 71 हैं। फिलीपींस में 41 भारतीय हैं, जबकि उनकी जेलों में थाईलैंड 23 और इंडोनेशिया 20 हैं।

ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के 62 मामले जेलों में बंद हैं, जबकि कनाडा और साइप्रस में 23 कैदी हैं। फ्रांस में 35, ग्रीस में 22, मालदीव में 24 और स्पेन में 49 भारतीय कैदी हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए, मंत्रालय ने कहा कि विदेशों में भारतीय मिशन / पोस्ट सतर्क रहते हैं और बारीकी से निगरानी करते हैं÷ स्थानीय कानूनों के उल्लंघन या स्थानीय कानूनों के कथित उल्लंघन के लिए विदेशों में भारतीय नागरिकों को जेल में डाल दिए जाने की घटनाएं हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जेल में बंद कैदियों को हर संभव कांसुलर सहायता प्रदान करने के अलावा, भारतीय मिशन और पोस्ट भी जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। मिशन और पोस्ट वकीलों का एक स्थानीय पैनल भी बनाए रखते हैं जहां भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में है।

शराब का नशा, 100 की स्पीड और गानों का शोर... 6 स्कूली बचों को रौंदा, 5 की मौत

नई दिल्ली । राजस्थान के जालोर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक तेज रफ्तार कार ने एक साथ 6 स्कूल बचों को रौंद दिया जिसमें से 5 की जान चली गई। दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार यहां के करड़ा में बुधवार शाम चार बजे स्कूल से लौट रहे ये बचे एक शराबी की कार के नीचे आ गए। बचे सड़क से काफी दूर चल रहे थे इसके बावजूद 100 की स्पीड से दौड़ रही कार ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। जांच में सामने आया है कि कार में करवाड़ा के सुरेश और अशोक कुमार सवार थे। कार सुरेश चला रहा था जो कि पकड़ा गया जबकि अशोक भाग निकला। दोनों नशे में धुत थे और तेज म्यूजिक के साथ 100 की स्पीड में गाड़ी चला रहे थे।

हादसे में एक भाई बहन समेत 5 की मौत हो गई जबकि एक बची गंभीर रूप से घायल है। ये बचे राजकीय उच माध्यमिक विद्यालय दांतवाड़ा में 9वीं और 10वीं में पढ़ते थे। वहां मौजूद लोगों ने बताया की कार ने पहले दो चक्कर लगाए और तीसरे चक्कर में बचों को कुचल दिया।

फ्लाइट में करें कोरोना गाइडलाइंस का पालन, वरना लग सकता है तीन महीने का बैन

नई दिल्ली । कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर देश में देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों की ढील के कारण ऐसा हो रहा है। लोग कोरोना गाइडलाइन्स का सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं। इस लिए अब सख्ताई बढ़ाते हुए उन लोगों की खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो हवाई यात्रा करते समय कोरोना मानदंडों का पालन नहीं करते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा है कि घरेलू उड़ानों में कोरोना गाइडलाइन्स का उल्लंघन करने वालों को तीन महीने तक यात्रा करने से रोका जा सकते हैस उन पर बैन लगा दिया जाएगा। विमानन नियामक छतष्ट के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि इस महीने तीन एयरलाइनों की घरेलू उड़ानों पर कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन करते पाए गए पंद्रह यात्रियों को एयरलाइन्स द्वारा तीन महीने के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 13 मार्च को एयरलाइंस से कहा था कि जो बार-बार चेतावनी के बावजूद अपने मास्क ठीक से नहीं पहनते हैं, उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए।

नियामक नियमों का पालन नहीं वाले यात्रियों को तीन से 24 महीनों के लिए यात्रियों पर (नो-फ्लाई सूची में डालकर) प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। हालांकि, इनमें से अधिकांश यात्रियों ने फ्लाइट में मास्क पहनने से इनकार कर दिया, दूसरों ने पीपीई गाउन पहनने से इनकार कर दिया, जो बीच की सीटों पर बैठने वालों के लिए अनिवार्य हैं। अधिकारियों ने कहा कि तीनों एयरलाइंस इन 15 यात्रियों को तीन महीने की अवधि के लिए अपनी नो-फ्लाई सूची में डाल सकती हैं।

सेना की जिप्सी में पलटने के बाद लगी आग 3 जवानों की मौत, 5 जवान घायल

जयपुर । पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के राजियासर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें सेना की एक जिप्सी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पहले जिप्सी पलटी और फिर उसमें आग लग गई। इस हादसे में जिप्सी में सवार 3 जवानों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। दुर्घटना में जवान बुरी तरह से झुलस गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 5 घायल जवानों को इलाज के लिए सूरतगढ़ के ट्रोमा अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया और फिर वहां से बृहस्पतिवार सुबह सेना के अस्पताल में ले जाया गया।

पुलिस के अनुसार दुर्घटना सूरतगढ़-छतरगढ़ रोड़ पर इंदिरागांधी नहर की 330 आरडी के पास बुधवार आधी रात बाद करीब 2 बजे हुआ । यहां सेना की एक जिप्सी अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। पलटने के बाद जिप्सी में भीषण आग लग गई। जिप्सी में सवार जवान बठिंडा की 47-एडी यूनिट के हैं। ये जवान युद्धाभ्यास के लिए श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ आए हुए थे। देर रात राजियासर से गुजर रहे थे कि अचानक चालक ने एक जानवर को बचाने के चक्कर में नियंत्रण खो दिया, सड़क पर पत्थर भी पड़ा हुआ था। जिससे जिप्सी पलट गई। इससे काफी तेज आवाज हुई तो आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 जवानों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया और घायल 5 जवानों को उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार दुर्घटना के बाद जिप्सी में सवार 3 जवान घायल होकर बेहोश हो गए, वे निकल नहीं सके तो जिंदा जल गए। वहीं 5 जवान निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन वे घायल हो गए। सेना ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। राजियासर थाना पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने फिलहाल जवानों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं।

भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार नदिया जिले में एक पार्टी कार्यकर्ता के परिवार के सदस्य से बात करते हुए, जिसकी कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी।

महिला अफसरों के लिए स्थायी कमिशन को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी, सेना के पैमानों को बताया, मनमाना और तर्कहीन

नई दिल्ली । भारतीय सेना और नौसेना में महिला अफसरों को स्थाई कमीशन की मांग को लेकर दायर याचिक पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना को निर्देश दिया है कि वह एक महीने के भीतर महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन देने पर विचार करे और नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए 2 महीने के भीतर इन्हें स्थायी कमीशन दे। सुप्रीम कोर्ट ने कह सेना में यह जारी रहेगा और वे सभी सुवाधिओं का लाभ उठाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट कमीशन के लिए महिला अफसरों के लिए बनाए गए मेडिकल फिटनेस मापदंड मनमाना और तर्कहीन बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना द्वारा अपनाए गए मूल्यांकन मापदंड महिलाओं के भेदभावा का कारण बनते हैं। भारतीय सेना में महिला अफसरों को स?थायी कमीशन देने संबंधी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 250 की सीलिंग को 2010 तक पार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन आंकड़ों को रिकॉर्ड पर रखा गया है, वो केस के बेंचमार्किंग को पूरी तरह से ध्वस्त करते हैं।

भारतीय सेना और नौसेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थाई आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेना द्वारा अपनाए गए मानकों की कोई न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। इस मामले को लेकर महिला अधिकारियों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सेना में एक करियार कई ट्रायल के साथ आता है। यह तब और मुश्किल हो जाता है जब समाज महिलाओं पर चाइल्टकेयर और घरेलू काम की जिम्मेदारी डालता है।

7 महिला अधिकारियों ने दायर की थी याचिका

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आज भारतीय सेना की 17 महिला अधिकारियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सेना ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद अभी तक महिला अधिकारियों को 50त तक स्थायी आयोग (पीसी) प्रदान नहीं किया है। सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी थी।

इस बार 6 लाख भक्त पहुंच सकते हैं अमरनाथ,अप्रैल से रिजस्ट्रेशन शुरू

नई दिल्ली । इस साल अमरनाथ यात्रा में 6 लाख शिवभक्तों के आवागमन की संभावना को देखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव, बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने बुधवार को सुरक्षित और परेशानी मुक्त अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक की। मुख्य सचिव ने कश्मीर और जम्मू के डिवीजनल कमिश्नरों को निर्देश दिया कि वे विशेष रूप से कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, रामबन, अनंतनाग, श्रीनगर, बालटाल में यात्रा मार्ग के साथ ट्रांजिट कैंपों में लगने वाली व्यवस्था की बारीकी से निगरानी करें।

उन्होंने कहा कि दोनों संभागीय प्रशासन छह लाख यात्रियों के आवागमन के उद्देश्य के साथ इंतजामों को सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने मंडलायुक्त कश्मीर और जम्मू को यात्रा रूट कठुआ, सांबा, जम्मू, उधमपुर, रामबन, अनंतनाग, श्रीनगर, बालटाल और चंदनबाड़ी में प्रबंधों की निगरानी करने को कहा।

जिला उपायुक्तों को संबंधित क्षेत्रों में ट्राजिस्ट कैंपों में यात्री क्षमता बढ़ाने को कहा गया है। इन कैंपों में सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। यात्रा से पूर्व सभी इंतजामों को सुनिश्चित बनाने को कहा गया। आगामी एक अप्रैल से यात्रा के लिए अग्रिम यात्री पंजीकरण शुरू किया जा रहा है।

56 दिवसीय अमरनाथ यात्रा 28 जून को सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ शुरू होगी, और हमेशा की तरह 22 अगस्त को रक्षा बंधन के दिन समाप्त होगी। इसके लिए अप्रैल के पहले सप्ताह से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे।

केरल नन केसः मानव तस्करी के आरोप में ननों को रेल से उतारा, बाद में झूठी पाई गई शिकायत

नई दिल्ली एजेंसी ।

दिल्ली से राउरकला जा रही एक ट्रेन से कुछ लोगों की शिकायत के शक पर दो ननों और किशोरियों को ट्रेन से उतार लिया गया। मानव तस्करी के शक में उतारी गई ननों को रेलवे पुलिस के सामने पेश किया गया। दोनो नन केरल की रहने वाली थीं। लोगों की शिकायत पर ननों को झांसी स्टेशन पर उतारा गया और लगभग एक घंटे पूछताछ करने के बाद दूसरी ट्रेन से रवाना कर दिया गया।

पूछताछ में शिकायत को झूठा पाया गया और उन्हें छोड़ दिया गया।

रेवले के एक प्रवक्ता ने कहा, 19 मार्च को, हमें एक ही कोच में दो युवा लड़कियों के साथ यात्रा कर रहीं दो नन के खिलाफ शिकायत मिली। उत्कल एक्सप्रेस के एक

यात्री ने हमारी हेल्पलाइन पर कॉल कर शिकायत की।

बाद में, एक लिखित शिकायत भी मिली थी। जांच के बाद, हमने पाया कि मानव तस्करी या किसी तरह का कोई मामला नहीं था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया और उन्हें वापस भेज दिया गया।

घटनाओं के बारे में बताते हए एक अधिकारी ने कहा कि 19 मार्च को लगभग 7ः45 बजे एक सूचना मिली थी कि उत्कल एक्सप्रेस द्वारा मानव तस्करी के एक संदिग्ध मामले में दो नन दो लड़कियों को ले जा रही हैं। इस सूचना के मिलने पर जीआरपी और आरपीएफ झांसी ने संयुक्त रूप से शाम 7ः52 बजे ट्रेन में एंट्री की थी।

ट्रेन में, दो लड़कियों को दो महिला यात्रियों के साथ यात्रा करते पाया गया और इस मामले में पूछताछ करने के लिए, चारों को ट्रेन से उतार दिया गया और आगे के सत्यापन के लिए राजकीय रेलवे पुलिस स्टेशन झाँसी लाया गया क्योंकि ठहराव का समय कम था।

अधिकारी ने कहा कि मामले को जीआरपी द्वारा सत्यापित किया गया और पाया गया कि शिकायत में लगे आरोप झूठे थे और उन्हें छोड़ दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया जिन्होंने उत्तर प्रदेश में झांसी में अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान केरल की ननों को कथित रूप से परेशान किया था।

शाह ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, मैं केरल के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस घटना के पीछे के दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी।

कर्नाटक के मंत्री बोले, कितने विधायकों के हैं अवैध संबंध, पता लगाने को होना चाहिए मोनोगैमी टेस्ट

नई दिल्ली । कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के. सुधाकर ने कहा है कि राय के सभी विधायकों का मोनोगैमी टेस्ट कराया जाना चाहिए ताकि पता लग सके कि कितने लोगों के अवैध संबंध हैं। उनके इस बयान के बाद से राय की राजनीति में उबाल आ गया है। विधानसभा में इस बयान पर हंगामे के बाद मंत्री ने सफाई देते हुए कहा है कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया है और यदि कोई आहत हुआ है तो वह इसके लिए दुख जताते हैं। सुधाकर ने बुधवार को पूर्व मंत्री रमेश जरकिहोली पर लगे आरोपों को लेकर कहा था, कांग्रेस और जेडीएस के वह विपक्षी नेता जो खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम और रामचंद्रदास के तौर पर पेश कर रहे हैं, मैं उन्हें एक चुनौती देता हूं। सभी 225 लोग एक जांच का सामना करें और पता चल जाएगा कि कौन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है

और कौन नहीं। इस टेस्ट में मैं भी शामिल रहूंगा।

बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए सुधार ने कहा, हर किसी के कैरेक्टर का पता चल जाएगा। जब मुख्यमंत्री थे तो किसने क्या किया था। हर चीज को सामने आने देना चाहिए। खैर, यह नैतिकता और मूल्यों का प्रश्न है। इसमें मंत्रियों, विधायकों और विपक्षी नेताओं सभी को शामिल करना चाहिए। के. सिद्धारमैया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी का नाम लेते हुए मंत्री ने कहा कि यदि उनकी अंतरात्मा सही है तो फिर उन्हें इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए और जांच के लिए तैयार रहना चाहिए।

उन्होंने कहा था, वे सभी सत्यवादी हरिशचंद्र हैं। केआर रमेश कुमार, वी मुनियप्पा, शिवकुमार, सिद्धारमैया, कुमारस्वामी, ये सभी मोनोगैमी टेस्ट कराएंगे। मैं उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए कहता हूं। सभी 225 लोगों का मोनोगैमी टेस्ट होना चाहिए। सत्य बाहर आ जाएगा। मैं इसके लिए तैयार हूं। दरअसल कांग्रेस की ओर से येदियुरप्पा सरकार के 6 मंत्रियों से इस्तीफे की मांग की गई थी। इन मंत्रियों में के. सुधाकर का नाम भी शामिल था। दरअसल सेक्स वीडियो के आरोप में इस्तीफा देने वाले पूर्व मंत्री रमेश जरकिहोली के समर्थन में मंत्रियों ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी।

कोरोना नियमों पर मुंबई पुलिस सख्त, मास्क न पहनने पर 2,03,000 लोगों से वसूले 4.06 करोड़

नई दिल्ली । देश और दुनिया में जमकर तबाही मचाने के बाद अब शुरू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर डराने लगी है। महाराष्ट्र की स्थिति इस समय अन्य रायों की तुलना में यादा बुरी है। बढ़ते मामलों के पीछे एक बड़ा कारण आम लोगों की लापरवाही भी है। ऐसे में प्रशासन को जुर्मानों के साथ सख्त होना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में अब तक, 2,03,000 लोगों से मास्क न पहनने पर जुर्माना लिया गया है। इस जुर्माने में अब तक 4.06 करोड़ रुपये वसूल किया गया है। मुंबई पुलिस के पीआरओ की ओर से ये जानकारी सामने आई है।

इधर, कोरोना संक्रमण के केसों में तेजी से इजाफा होने के चलते भारत सरकार ने वैक्सीनेशन के अभियान को तेज करने का फैसला लिया है। 1 अप्रैल से 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाना है। इसके बाद जल्दी ही अन्य लोगों का नंबर आ सकता है।

इसके अलावा सरकार अब कोरोना वैक्सीन का एक्सपोर्ट नहीं करेगी ताकि तेजी से देश में टीकाकरण हो सके। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने नाम उजागर ने करने की शर्त पर कहा कि एक्सपोर्ट पर किसी तरह का बैन नहीं होगा, लेकिन घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद ही दूसरे देशों को वैक्सीन की सप्लाई की जाएगी। इसके अलावा भविष्य में टीकों के तेजी से उत्पादन पर भी एक्सपोर्ट का फैसला निर्भर करेगा।

एक सूत्र ने कहा, हमने दुनिया भर के देशों को कोरोना वैक्सीन की कॉमर्शियल सप्लाई की है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेंगे। दूसरे देशों से हुई सभी कॉमर्शियल डील्स और एक्सपोर्ट कमिटमेंट्स का सम्मान किया जाएगा। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता देश में यादा से यादा लोगों का वैक्सीनेशन किए जाने की है। भारत में आने वाले दिनों में वैक्सीन के उत्पादन में इजाफा होगा। इसके अलावा कुछ और टीकों के इमरजेंसी में इस्तेमाल को मंजूरी दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में करीब दो महीने बाद सरकार की ओर एक्सपोर्ट के फैसले को लेकर समीक्षा की जाएगी।

एसीबी टीम को देख पिंडवाड़ा तहसीलदार ने किया दरवाजा बन्द, जला दिए रिश्वत ली काली कमाई

जोधपुर । सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील के रेवन्यू इंस्पेक्टर(आरआई)को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जब आरआई ने रिश्वत मामले में तहसीलदार का नाम लिया तो उसने अपने आप को मकान में बंद कर काली कमाई के रुपए में आग लगा दी। एसीबी की टीम ने तहसीलदार को मकान का दरवाजा तोड़कर गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि नोटों के अलावा कुछ दस्तावेजों को भी तहसीलदार ने आग लगा दी थी।

जोधपुर के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम संभाग के सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसीलदार को रिश्वत की राशि लेते पकड़ने पहुची। जिसकी भनक घूसखोर तहसीलदार को लगने पर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और रिश्वत राशि को रसोई में चूल्हे पर जलाने का प्रयास किया। जिसके बाद स्थानीय पुलिस और एसीबी की टीम में कटर के द्वारा दरवाजे को काट भीतर प्रवेश किया गया। जहां रसोई के चूल्हे पर रिश्वत में लिए गए रुपए जलते दिखाई दिए। एसीबी की टीम ने आंवले की छाल का ठेका दिलाने की एवज में माँगी गयी एक लाख रुपये की रिश्वत के आरोप में घूसखोर तहसीलदार कल्पेश जैन को हिरासत में लिया है। इस संबद्ध में उससे पूछताछ जारी है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उप महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर डॉ विष्णुकांत ने बताया कि परिवादी ने एक लिखित शिकायत देकर आवले की छाल का ठेका लेने के सम्बंध में पिंडवाड़ा तहसीलदार कल्पेश कुमार जैन द्वारा पर्वत सिंह राजस्व निरीक्षक, वृत भांवरी, पिण्डवाड़ा, के मार्फत 1,00,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। इस का गोपनीय रूप से सत्यापन करवाया जाने पर परिवादी से आवले की छाल का ठेका दिलवाने की एवज में कल्पेश कुमार तहसीलदार पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही के कहेनुसार पर्वत सिंह राजस्व निरीक्षक, द्वारा रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। रिश्वत की राशि प्राप्त करने पर विभागीय कार्रवाई के तहत एसीबी की टीम ने तहसीलदार आवास पर दबिश दी जिसकी भनक कल्पेश जैन को होने पर उसने दरवाजा बंद कर दिया। पुलिस के द्वारा समझाने के बाद भी दरवाजा नहीं खोले जाने पर कटर के माध्यम से दरवाजे को काटा गया, जहां कल्पेश जैन घर के भीतर ही छुपा था। एसीबी टीम और पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए तहसीलदार के सरकारी आवास में प्रवेश किया जहां सरकारी आवास के किचन में रिश्वत राशि के रूप में ली गई भारतीय मुद्रा चूल्हे पर जलती पाई गई। जिसके बाद आग को बुझाने का प्रयास किया गया और बचे हुए नोटों को बतौर सबूत एसीबी द्वारा कलेक्ट किया गया। पुलिस ने तहसीलदार कल्पेश जैन को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ जारी है। एसीबी ने आमजन की जागरूकता के लिए फिर से अपना हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिस पर पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

अहमदाबाद परिसर कंटेनमेंट जोन घोषित, गुजरात में 1790 नए मामलों की पुष्टि

अहमदाबाद । कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। बीते दो दिनों में आईआईएम में कोरोना के 23 केस सामने आए हैं। गुजरात में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण कोविड-19 वायरस के नये स्ट्रेन तथा स्थानीय निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने को माना जा रहा है।

अकेले अहमदाबाद में पिछले दो दिन में 500 नये केस सामने आए जबकि गुजरात में पिछले 24 घंटे में 1790 केस सामने आए। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के परिसर को 23 केस सामने आने के बाद कंटेनमेंट जोन में परिवर्तित कर दिया गया है।

पिछले दो दिन में जांच के दौरान पहले 10 के सामने आए तथा उसके बाद आसपास के ब्लॉक के छात्रों की जांच की गई तो तेरह और नए केस सामने आए। गुजरात में कोरोना संक्रमण के अब तक दो लाख 92169 के सामने आ चुके हैं जबकि 4466 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के चलते गुजरात में 8 लोगों की मौत हुई है जो 24 घंटे में दोगुनी हुई है। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, राजकोट से बड़ोदरा सहित बड़े शहरों में कोरोना के 70त के सामने आ रहे हैं।

राज्य में एक बार फिर कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 8825 के पार चली गई है। करुणा के चलते गुजरात में आत्महत्या की दर में करीब 7 फ़ीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है।

अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट तथा सूरत शहर के आत्महत्या के आंकड़ों में पता चलता है कि 2018 -19 तथा 2019 -20 के आंकड़ों में इजाफा होता नजर आ रहा है।

पश्चिम बंगाल के तीन दिवसीय दौर पर जाएंगे शरद पवार, 1 अप्रैल से ममता बनर्जी के समर्थन में करेंगे प्रचार

मुंबई । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपना समर्थन देंगे और अगले सप्ताह राज्य में चुनाव प्रचार करेंगे। पश्चिम बंगाल के तीन दिवसीय दौरे के दौरान एनसीपी प्रमुख रैलियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे।

महाराष्ट्र राकांपा के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के कार्यक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि वह 1 अप्रैल से राज्य की तीन दिवसीय यात्रा पर होंगे, विभिन्न रैलियों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और तृणमूल भवन में ममता बनर्जी और टीएमसी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में मतदाताओं को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओर से कई घोषणाएं की गई हैं। भाजपा नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह, और योगी आदित्यनाथ राज्य में कई सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे, जबकि मिथुन चक्रवर्ती और गौतम गंभीर रोड शो करेंगे।पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान जारी है जिसे लेकर भाजपा और सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच विभिन्न मुद्दों पर एक-दूसरे के साथ कई बार भिड़ चुके हैं। टीएमसी के कई सदस्यों ने भाजपा का दामन थामा है और भाजपा के कई सदस्य टीएमसी में शामिल हुए हैं।

बता दें कि 294 सदस्यीय राज्य विधानसभा सीटों के चुनाव 27 मार्च से शुरू होकर आठ चरणों में खत?म होंगे। पहले चरण में पश्चिम बंगाल की 294 में से 30 सीटों पर 27 मार्च को मतदान होगा । दूसरे चरण में 30 सीटों पर एक अप्रैल को वोट डालो जाएंगे तीसरे चरण में 31 सीटों पर 6 अप्रैल को, चौथे चरण में 44 सीटों पर 10 अप्रैल को, पांचवे चरण में 45 सीटों पर 17 अप्रैल को, छठे चरण में 43 सीटों पर 22 अप्रैल को, सातवें चरण में 36 सीटों पर 26 अप्रैल को और आठवें चरण में 35 सीटों पर 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। नतीजों की घोषणा 2 मई को की जाएगी।

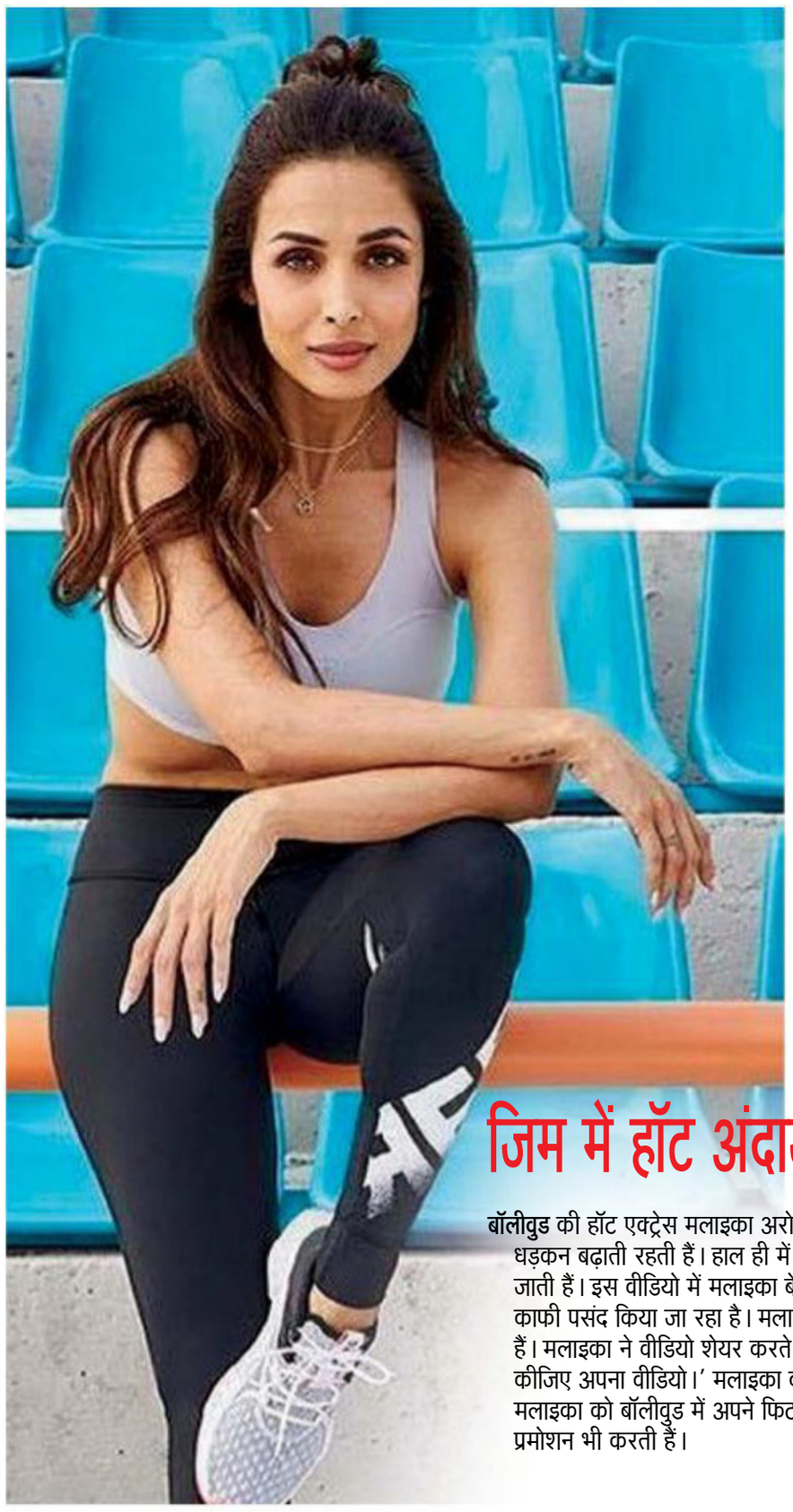

महेश बाबू संग पर्दे पर रोमांस करेंगी जाह्नवी कपूर

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना रही हैं। हाल ही में उनकी फिल्म 'रूही' रिलीज हुई है, जिसमें उनकी एक्टींग की जमकर तारीफ की जा रही है। वहीं अब खबर आ रही है कि जाह्नवी जल्द ही पर्दे पर साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के साथ नजर आ सकती हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म से महेश बाबू बॉलीवुड में कदम रख सकते हैं। वहीं इस प्रोजेक्ट के निर्माता करण जौहर हैं। उन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। खबरों के अनुसार इस बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट के लिए करण जौहर एक यंग डायरेक्टर की तलाश कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग जल्दी से जल्दी पूरी करने की भी तैयारी की जा रही है। मेकर्स इस फिल्म की शूटिंग महज 60 दिनों के अंदर पूरी कर देना चाहते हैं। करण जौहर की फिल्म 'धड़क' से ही जाह्नवी ने बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद उन्हें करण की हॉरर फिल्म 'घोस्ट स्टोरीज' में देखा गया। फिर करण, जाह्नवी के साथ फिल्म 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' लेकर आए। बता दें कि महेश बाबू के पिता कृष्णा और जाह्नवी कपूर की मां श्रीदेवी ने साथ में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। फैंस को दोनों की जोड़ी और केमिस्ट्री बहुत पसंद आती थी। अब फैंस को महेश बाबू और जाह्नवी से भी वही उम्मीदें हैं।

जिम में हॉट अंदाज में डांस करती नजर आईं मलाइका अरोरा

बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस मलाइका अरोरा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह अपनी हॉट तस्वीरों और वीडियो से फैंस के दिल की धड़कन बढ़ाती रहती हैं। हाल ही में मलाइका का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो जिम में वर्कआउट करते हुए डांस करने लग जाती हैं। इस वीडियो में मलाइका बेहद हॉट अंदाज में कमर मटकाती हुई नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर उनके इस वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है। मलाइका वीडियो में शॉर्ट पेंट्स और स्पोर्ट्स ब्रा पहनी हुई हॉट स्टाइल में डांस करती हुई नजर आ रही हैं। मलाइका ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'वीकएंड पर मैं ये मस्ती भरा डांस कर रही हूं। देखें आप क्या करते हैं। शेयर कीजिए अपना वीडियो।' मलाइका की गिनती कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस में होती हैं जो अपनी फिटनेस को लेकर काफी कॉन्सियस हैं। मलाइका को बॉलीवुड में अपने फिटनेस और हॉट पर्सनालिटी के लिए भी जाना जाता है। इसी के चलते वो कई सारे ब्रैंड्स का प्रमोशन भी करती हैं।

पर्दे पर फिर दिखेगी दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन की जोड़ी

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण जल्द ही फिल्म 'द इंटर्न' में नजर आने वाली हैं। यह फिल्म हॉलीवुड मूवी 'द इंटर्न' का हिन्दी रीमेक होगी। इस फिल्म में दीपिका के अलावा दिवंगत एक्टर ऋषि कपूर को साइन किया गया था। ऋषि कपूर के निधन के बाद इस फिल्म पर ब्रेक लग गया। ऋषि फिल्म का एक अहम हिस्सा थे, जिनके बिना फिल्म की शूटिंग होना नामुमिक था। अब खबर आ रही है ?मेकर्स ने फिल्म पर काम शुरू कर दिया है और फिल्म में ऋषि कपूर की जगह सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को साइन किया गया है। खबरों के मुताबिक फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया, ऋषि कपूर के निधन के बाद द इंटर्न की हिन्दी रीमेक पर बड़ा ब्रेक लग गया था। इसका साफ मतलब यही था कि कास्ट का एक अहम सदस्य कम हो गया है और मेकर्स को नई कास्ट के बारे में विचार करना होगा। इसमें थोड़ा समय लगा लेकिन मेकर्स ने अब फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को साइन कर लिया है और जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू करने के बारे में विचार कर रहे हैं। फिल्म पीकू की अपार सफलता के बाद एक बार फिर से द इंटर्न में फैंस दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन को साथ देखेंगे। बीते दिनों दीपिका ने कहा था कि द इंटर्न एक खूबसूरत रिलेशनशिप की कहानी है. फिल्म एक लाइट ड्रामा कॉमेडी है। वर्क फ्रंट की बात करें तो दीपिका पादुकोण जल्द ही फिल्म 83 में रणवीर कपूर के साथ नजर आने वाली हैं। इसके अलावा वह शकुन बत्रा की फिल्म में भी दिखेंगी। वहीं अमिताभ बच्चन फिल्म, चेहरे, झुंड और ब्रह्मास्त्र में नजर आने वाले हैं।

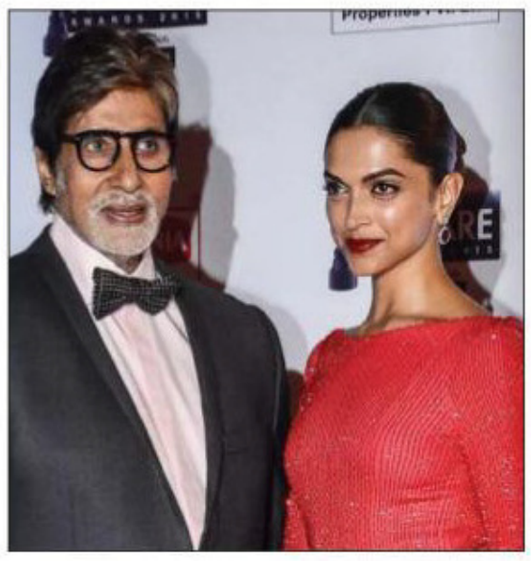

आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान बोलीं- एक्टर्स मास्क नहीं पहन सकते इसलिए उन्हें...

देश में कोरोनावायरस का प्रकोप एक बार फिर बढ़ गया है। कई बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स भी इस महामारी की चपेट में आ रहे हैं। वहीं कोरोनावायरस से लड़ने के लिए सरकार ने वैक्सीनेशन को और तेज कर दिया है। इसी बीच आलिया भट्ट की मां और एक्ट्रेस सोनी राजदान ने कोरोना वैक्सीन को लेकर अपनी बात कही है। दरअसल, सोनी राजदान ने बिजनेसमैन सुहैल सेठ की उस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए अपनी बात कही, जिसमें सेठ ने लिखा कि भगवान की खातिर सभी का वैक्सीनेशन करवाइए। जिसको भी वैक्सिनेशन करवाना हो, उसे यह टीका लगाया जाए। सुहैल सेठ की पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए सोनी राजदान ने लिखा- सरकार को शीघ्र प्रभाव से कलाकारों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि कलाकार मास्क नहीं पहन सकते। सोनी राजदान ने कहा- ये काम नहीं एक पेशा है। लोगों को सही काम करने की जरूरत है। दूसरे लोग अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन केवल कलाकार हैं जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते। सोनी राजदान ने एक और ट्वीट में लिखा- हर एक्टर बड़ा सुपरस्टार नहीं होता है, इसलिए जो लोग शिकायत कर रहे हैं, उन्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। ऐसे लोगों को कंटेंट देखना बंद कर देना चाहिए। ये एक्टर्स की जिंदगी को खतरे में डालकर बनता है और वो हमेशा जोखिम में रहते हैं। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोनी राजदान की बेटी आलिया भट्ट नेपोटिज्म के लिए जमकर ट्रोल की गई थीं। इस पर सोनी राजदान ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कमेंट्स सेक्शन ऑफ कर दिया था। सोनी राजदान ने कमेंट सेक्शन बंद करते हुए कहा कि जब नफरत करने वालों को कोई दूसरा निशाना मिल जाएगा तब वो अपना कमेंट सेक्शन ऑन कर देंगी।

कियारा आडवाणी कर रही हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा को डेट

रिलेशनशिप पर की खुलकर बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी का नाम कई बार सिद्धार्थ मल्होत्रा संग जोड़ा जा चुका है। दोनों को साथ में लंच और डिनर डेट पर भी स्पॉट किया गया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कियारा आडवाणी ने अपने रिलेशनशिप स्टेटस पर खुलकर बात की। फिल्मफेयर संग बातचीत में जब कियारा आडवाणी से सिद्धार्थ मल्होत्रा को डेट करने को लेकर पूछा गया तो एक्ट्रेस इस सवाल पर चुप रहीं। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि आखिरी बार वह कब डेट पर किसी के साथ गई थीं तो इस पर उनका जवाब सुनकर फैन्स को शॉक लगा। कियारा आडवाणी ने कहा, 'आखिरी बार मैं जब डेट पर गई थी तो वह इसी साल थी। इस साल के दो महीने पहले ही मैं डेट पर गई हूं। तो मुझे लगता है कि आप लोग मैथ कर चुके होंगे या आइडिया लगा चुके होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। मालूम हो कि हाल ही में कियारा आडवाणी ने एक तस्वीर में वह लैक और दूसरे में वाइट आउटफिट पहने हैं। दोनों ही फोटोज में वह कमाल दिख रही हैं। तस्वीर को 1 घंटे के अंदर 6 लाख से ज्यादा लाइस मिल चुके हैं। यह फोटोज फिल्मफेयर कवर शूट की हैं। कियारा आडवाणी के वर्क फ्रंट पर बात करें तो वह 'शेरशाह', 'भूल भुलैया 2', 'जुग जुग जीयो' जैसी फिल्मों में नजर आएंगी। 'शेरशाह' परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म में कियारा के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म 3 जुलाई 2020 में रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से इसकी रिलीज टल गई। फिल्म अब 2 जुलाई 2021 को सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी।

पिता को याद कर भावुक हुईं ऐश्वर्या राय

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने अपने पिता कृष्णाराज राय को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया है। पिता की पुण्यतिथि पर एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर की। इसके साथ ही ऐश्वर्या ने एक इमोशनल नोट भी लिखा है। एक्ट्रेस अपने पिता के बेहद करीब थीं। पोस्ट के साथ ही उन्होंने मां-पापा और बेटी के साथ तस्वीर शेयर की। परिवार के साथ तस्वीर शेयर करने के साथ ही उन्होंने लिखा था कि 'हम आपसे बेहद प्यार करते हैं। हमेशा और उसके आगे भी।' ऐश्वर्या राय ने पिता कृष्णाराज राय की तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाए गए हैं। दूसरी तस्वीर में ऐश्वर्या बेटी आराध्या और मां के साथ हैं। तीनों कृष्णाराज राय की तस्वीर के पास हैं और ऐश्वर्या सेल्फी ले रही हैं।

दूसरे वनडे मैच में ऐसी हो सकती है भारत की प्लेइंग इलेवन

बदलाव करने के लिए मजबूर है टीम इंडिया

नई दिल्ली। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मैच शुक्रवार 26 मार्च को खेला जाना है। इससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि भारतीय टीम किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतर सकती है। टीम को दूसरे वनडे मैच के लिए कम से कम एक बदलाव जरूर करना होगा, क्योंकि मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर चोटिल होकर वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं।

दाएं हाथ के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के चोटिल होने की स्थिति में भारतीय टीम के पास मध्यक्रम की बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज रिषभ पंत और पहली बार वनडे टीम में शामिल किए गए दाएं हाथ के बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव हैं, जो नंबर चार पर बल्लेबाजी करने में सक्षम हैं। शुभमन गिल भी वनडे टीम का हिस्सा हैं, लेकिन वे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी अभी पुख्ता नहीं है।टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को भी पहले वनडे मैच में चोट लगी थी, लेकिन वे दूसरा वनडे मैच खेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको फैक्टर नहीं हुआ है। वहीं, उनके जोड़ीदार के रूप में फिर से शिखर धवन को देखा जा सकता है। इसके अलावा तीन नंबर पर विराट कोहली होंगे, जबकि चौथे नंबर के लिए रिषभ पंत और सूर्यकुमार में जंग है, लेकिन कप्तान कोहली अनुभवी रिषभ पंत के साथ जाना पसंद करेंगे।पांचवें नंबर पर फिर से केएल राहुल को देखा जा सकता है, जबकि छठे नंबर पर मैच फिनिशर के तौर पर हार्दिक पांड्या और सातवें नंबर पर उनके भाई क्रुणाल पांड्या को मौका दिया जाएगा। गेंदबाज के तौर पर शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव को फिर से मौका मिलने के चांस हैं। भारतीय टीम पहला मुकाबला जीत चुकी है। ऐसे में दूसरा मुकाबला जीतकर भारत सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करना चाहेगा।

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली (कप्तान), केएल राहुल, रिषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, क्रुणाल पांड्या, शार्दुल ठाकुर, भुवनेश्वर कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव

आईपीएल 2021 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की नई जर्सी आई सामने, सशस्त्र बलों को है समर्पित

चेन्नई। इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के अगले सीजन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके ने अपनी नई जर्सी को लॉन्च कर दिया है। नौ अप्रैल से शुरू होने जा रही इस लीग के 14वें सीजन के लिए बुधवार को सीएसके ने अपनी नई जर्सी लॉन्च की। इस बार सीएसकी की जर्सी खास है, क्योंकि महेंद्र सिंह धौनी की कप्तानी वाली टीम ने अपनी नई जर्सी में सेना को सम्मान देते हुए उसका कैमोफ्लेज भी जोड़ा है। तीन बार की आइपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान धौनी ने टीम की नई जर्सी को लॉन्च किया, जिसका वीडियो सीएसके ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट किया है। हमेशा की तरह चेन्नई की जर्सी पीले रंग की है, लेकिन कंधों के ऊपर इंडियन आर्मी का कैमोफ्लेज भी जोड़ा गया है। सीएसके ने अपने एक बयान में नई जर्सी के लॉन्च को लेकर कहा कि टीम ने 2008 में पहले संस्करण के बाद से अपनी जर्सी को फिर से डिजाइन किया है।

सीएसके के सीईओ केएस विश्वनाथन ने इस बारे में कहा, 'सशस्त्र बलों की महत्वपूर्ण और निस्वार्थ भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के तरीकों को खोजने के लिए कुछ समय पहले से ही यह हमारे दिमाग में था। यही कारण है कि इस बार सेना का कैमोफ्लेज सीएसके ने अपनी जर्सी में प्रयोग किया है।' वहीं, इंडिया सीमेंट्स, जो सीएसके की मालिकाना हक वाली कंपनी है, उसके 75 साल पूरे होने की वजह से भी जर्सी में बदलाव हुआ है। गौरतलब है कि एमएस धौनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010, 2011 और 2018 में आइपीएल का खिताब जीता है। 11 आइपीएल सीजन खेलकर सबसे ज्यादा 10 बार प्लेऑफ में पहुंचने वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स आठ बार फाइनल भी खेल चुकी है, लेकिन पिछले साल संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में खेले गए आइपीएल के प्लेऑफ में टीम जगह बनाने में असफल रही थी।

जोकोविच को बदनाम करने की साजिश:सर्बियन मॉडल नतालिया ने कहा- वर्ल्ड नंबर-1 टेनिस प्लेयर की जिंदगी बर्बाद करने के लिए 50 लाख रुपए का ऑफर मिला

नई दिल्ली। सर्बियन मॉडल नतालिया स्केकिच ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा है कि उन्हें दुनिया के नंबर एक टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच के साथ सेक्स टेप बनाने के लिए 50 लाख रुपए का ऑफर मिला था। इस सेक्स टेप का मकसद जोकोविच की जिंदगी बर्बाद करना था। इंस्टाग्राम स्टार और मॉडल नतालिया ने यूरोपियन मैग्जीन स्वेट एंड स्कैंडल के साथ हुई बातचीत में यह खुलासा किया।

नतालिया ने क्या कहा?

नतालिया ने कहा कि मुझसे एक व्यक्ति ने संपर्क किया था। मैं उसे पहले से पहचानती थी। पहले उसने मुझे डेट पर जाने के लिए कहा। इस दौरान मुझे लगा कि वह मुझसे कोई बिजनेस डील करना चाहता है। लेकिन बाद में मुझे यह समझ में आ गया कि दरअसल वह शख्स मेरे से जोकोविच की जिंदगी बर्बाद करवाना चाहता था। उसने मुझसे कहा था कि मुझे जोकोविच को बहलाकर एक रोमांटिक जगह पर ले जाना है और उसके साथ एक सेक्स टेप शूट करना है। इसके बदले में उसने मुझे 70 हजार डॉलर (करीब 50 लाख रुपए) और एक विदेश ट्रिप का ऑफर दिया था।

इलेक्ट्रीशियन की बेटी ने जीता गोल्ड: भोपाल की शूटर चिंकी यादव ने कहा- पहला वर्ल्ड कप मेडल जीतकर खुश हूं, टॉप शूटर मनु और राही के होने से दबाव नहीं था

नई दिल्ली। दिल्ली में चल रहे ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में भोपाल की रहने वाली चिंकी यादव ने 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। भास्कर से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह वर्ल्ड कप में उनका पहला मेडल है। चिंकी ने कहा कि गोल्ड के रूप में अपना पहला वर्ल्ड कप मेडल जीतकर वे बेहद खुश हैं। चिंकी के पिता मेहताब सिंह यादव पेशे से भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में इलेक्ट्रीशियन हैं। इस वजह से वे बचपन से ही कई खेलों को देख रही हैं। चिंकी ने शूटिंग वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की ही टॉप शूटर मनु भाकर और राही सरनोबत को हराया। उन्होंने कहा कि मनु और राही के होने के बावजूद वे दबाव में नहीं थीं। देखिए मैच प्रेशर तो सभी खिलाड़ियों के ऊपर होता है। मनु और राही के होने से दबाव नहीं था। फाइनल में होने का दबाव था। मैं नर्वस थी। मैच के दौरान जो विचार आते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए मैं मेडिटेशन करती हूं। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट भी जुड़ीं थीं।

विराट कोहली से दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज की कुर्सी छीन सकता है ये पाकिस्तानी खिलाड़ी

लाहौर। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर दो बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर आजम ने भारतीय टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली इस समय आइसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर वन बल्लेबाज हैं और उसके बाद बाबर आजम का नाम है। हालांकि, पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के इरादे अब भारतीय कप्तान विराट कोहली को पछाड़ने के हैं, क्योंकि दोनों में अब बहुत कम फासला बचा है।

साउथ अफ्रीका के दौरे पर पाकिस्तान की टीम को तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है, जिसमें शानदार प्रदर्शन करने के बाद बाबर आजम वनडे क्रिकेट में नंबर वन बल्लेबाज बन सकते हैं। आइसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग के अनुसार बाबर आजम 837 रेटिंग प्वाइंट्स के साथ रोहित शर्मा (836 रेटिंग प्वाइंट्स) को पछाड़कर दूसरे नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं। उनसे आगे केवल विराट कोहली हैं, जिनके खाते में 868 रेटिंग प्वाइंट्स हैं। बाबर आजम आगामी पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज में कोहली से नंबर 1 स्थान के करीब पहुंच सकते हैं या दावा भी कर सकते हैं।

पाकिस्तान के मजहर अरशद ने कहा है, 'बाबर आजम (837 रेटिंग अंक) अब ICC ODI रैंकिंग में दूसरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं और उनके पास दक्षिण अफ्रीका के साथ आगामी श्रृंखला में नंबर एक स्थान पर विराट कोहली (868 अंक) को पास होने या फिर उनको पीछे छोड़ देने का अवसर होगा।

उन्होंने कहा है, 'यह एकमात्र प्रभावशाली कमाल नहीं है, जो 26 वर्षीय पाकिस्तानी कप्तान ने हासिल किया है।

बाबर आजम को एकमात्र पाकिस्तानी बल्लेबाज होने का गौरव प्राप्त है जो खेल के सभी प्रारूपों में आईसीसी के बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल हैं। टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में बाबर आजम तीसरे स्थान पर हैं, जबकि टेस्ट प्रारूप में, वह दुनिया के छठे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। वनडे में वे दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं।'

शूटिंग वर्ल्डकप: एलावेनिल ने 5 खेलों में हाथ आजमाया, फिर शूटिंग को अपनाया

भोपाल । 21 साल की एलावेनिल वलारिवान 10 मीटर एयर राइफल में दुनिया की नंबर-1 शूटर हैं। उन्होंने हाल ही में दिव्यांश सिंह पंवार के साथ 10 मी राइफल मिक्स्ड में गोल्ड जीता था। उनकी बचपन से ही खेलों में रुचि थी। एथलेटिक्स, बैडमिंटन, जूडो, हैंडबॉल और कबड्डी में हाथ आजमाए। स्टेट में मेडल भी जीते। पहली बार शौकिया तौर पर शूटिंग की। यह खेल पसंद आया। फिर गन फॉर ग्लोरी एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू की। इस चैंपियनशिप के बाद ध्यान इस माह भोपाल में होने वाली सीनियर नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप पर है। कोरोना की वजह से चीजें बदल रही हैं। आपको उनके हिसाब से चलना होता है कुछ खास फर्क नहीं दिखा। मुझे अपने देश के निशानेबाजों से ही ज्यादा चुनौती मिली है। इसके पीछे कड़ी मेहनत और टीम वर्क होता है। हम जितना काम टेक्निक पर करते हैं, उतना ही मेंटल और फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देते हैं। मैं 3 घंटे ट्रेनिंग, 2 घंटे वर्कआउट, एक घंटे माइंड ट्रेनिंग करती हूं। ट्रेनिंग में 5-6 घंटे का समय देती हूं।

इस खिलाड़ी को मिल सकती है दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी, जल्द लिया जाएगा फैसला

नई दिल्ली। भारतीय टीम के लिए इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए वनडे सीरीज के पहले मैच में दाएं हाथ के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को फील्डिंग के दौरान चोट लगी थी। श्रेयस अय्यर के कंधे में फ्रैक्चर हुआ है, जिसके कारण वे अगले कुछ महीने क्रिकेट की दुनिया से दूर रहेंगे। ये निजी तौर पर श्रेयस अय्यर के लिए बड़ा झटका तो है ही, साथ ही साथ दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि टीम को नया कप्तान चुनना होगा।

दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी पिछले तीन सत्रों से करते आ रहे श्रेयस अय्यर इस बार टीम के साथ नहीं होंगे। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स फ्रेंचाइजी को जल्द से जल्द टीम के नए कप्तान का ऐलान करना होगा, क्योंकि 9 अप्रैल से आइपीएल का नया सीजन शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि दिल्ली की टीम एक बार फिर से युवा खिलाड़ी को टीम की कप्तानी सौंप सकती है और ये युवा खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत हैं।

साल 2018 के करीब आधे सत्र के बाद जब गौतम गंभीर ने दिल्ली की टीम की कप्तानी छोड़ी थी तो उस समय दिल्ली की फ्रेंचाइजी ने 23 साल के युवा श्रेयस अय्यर को टीम का कप्तान बनाया था। वहीं, आइपीएल में सभी जानकारी प्राप्त कर रही है। टीम के मालिक, मुख्य कोच इस बात पर अंतिम विचार करेंगे कि हमारा कप्तान होगा, लेकिन जाहिर है कि उप-कप्तान ऋषभ पंत को कप्तान होना चाहिए। पंत के साथ, दिल्ली कैपिटल्स में अजिंक्य रहाणे, स्टीव स्मिथ, शिखर धवन और आर अश्विन जैसे कुछ अन्य उम्मीदवार भी कप्तान के तौर हैं, जिनके पास अतीत में आइपीएल फ्रेंचाइज़ी का नेतृत्व करने का अनुभव है, लेकिन सामने आ रहा है कि दिल्ली कैपिटल्स के रिषभ पंत के साथ आगे जाने की संभावना है। सूत्र के अनुसार, दिल्ली कैपिटल प्रबंधन इस सप्ताह के अंत से पहले नए कप्तान के नाम की घोषणा करने की संभावना है।

इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज ही नहीं, बल्कि आईपीएल 2021 से भी बाहर हुए श्रेयस अय्यर

पुणे। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में उतरने से पहले भारतीय खेमे से एक बुरी खबर सामने आ रही है। जी हां, भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ शुरुआती वनडे में कंधे की हड्डी खिसकने के कारण यहां चल रही सीरीज में नहीं खेल पाएंगे। इतना ही नहीं, नौ अप्रैल से शुरू हो रहे आइपीएल के 14वें सीजन से भी उनको बाहर होना पड़ा है।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के सूत्रों ने बताया कि अय्यर को बायें कंधे की सर्जरी करानी होगी, जिसकी वजह से वह कम से कम चार महीने क्रिकेट से दूर रहेंगे। बोर्ड के एक सूत्र ने कहा कि उसे ऑपरेशन कराना होगा। लगता है कि आइपीएल के पहले हाफ से ही नहीं, बल्कि वह पूरे आइपीएल से बाहर रहेंगे। उन्हें नेट्स पर लौटने में कम से कम चार महीने लगेंगे। वह काफी दर्द में है।

श्रेयस को इंग्लिश काउंटी टीम लंकाशायर के लिए भी उनका वनडे टूर्नामेंट खेलना है। लंकाशायर ने सोमवार को ही उनके साथ करार का एलान किया था। काउंटी सत्र 23 जुलाई से शुरू होगा। श्रेयस को इंग्लैंड की पारी के आठवें ओवर में चोट लगी जब तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की गेंद पर जॉनी बेयरस्टो के शॉट को रोकने के लिए डाइव किया। वह कंधे को पकड़कर मैदान से बाहर निकल गए और काफी दर्द में दिख रहे थे।आइपीएल में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करनी थी। मुंबई का यह 26 साल का खिलाड़ी बल्लेबाजी करते हुए महज छह रन बनाकर आउट हो गया था। श्रेयस ने पिछले चरण में दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में पहुंचाया था। कंधे के अपनी जगह से खिसकने से उबरने के लिए कम से कम छह हफ्तों का समय लगता है और अगर सर्जरी करानी पड़ती है तो और ज्यादा समय लगता है। उनकी अनुपस्थिति में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी रिषभ पंत, अजिंक्य रहाणे, ऑस्ट्रेलियाई स्टीव स्मिथ या सीनियर ऑफ स्पिनर आर अश्विन को सौंपी जा सकती है।

> भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) के सूत्रों ने बताया कि अय्यर को बायें कंधे की सर्जरी करानी होगी, जिसकी वजह से वह कम से कम चार महीने क्रिकेट से दूर रहेंगे। बोर्ड के एक सूत्र ने कहा कि उसे ऑपरेशन कराना होगा।

भारत-पाकिस्तान 8 साल बाद खेलेंगे क्रिकेट सीरीज ?: पीसीबी 3 मैच की सीरीज की तैयारी में जुटा, अगले हफ्ते आईसीसी की बैठक में लिया जा सकता है फैसला

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान इस साल 3 मैच की टी-20 सीरीज खेल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो 8 साल बाद दोनों टीमें किसी द्विपक्षीय सीरीज में भिड़ेंगी। दोनों के बीच पिछली टी-20 और वनडे सीरीज दिसंबर, 2012 में खेली गई थी। टी-20 सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही थी, वहीं वनडे सीरीज को पाकिस्तान ने 2-1 से जीता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी के मुताबिक उन्हें इसके लिए तैयारी करने को कहा गया है।

अगले हफ्ते होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बैठक में इसको लेकर बातचीत हो सकती है, वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अभी इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। 30 मार्च को भारतीय विदेश मंत्री और पाकिस्तानी विदेश मंत्री की मुलाकात हो सकती है। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज पर सहमति बन सकती है।

टी-20 सीरीज के लिए 6 दिन के विंडो की तलाश

पाकिस्तानी अखबार डेली जंग की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों देशों के बीच इस साल मुकाबला मुमकिन है। अखबार ने PCB के एक सूत्र के हवाले सेबताया कि पहले तो अधिकारी ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पर बाद में उन्होंने बताया कि दोनों टीमों के बीच 3 मैच की टी-20 सीरीज हो सकती है और इसके लिए 6 दिन के विंडो की तलाश जारी है।

2012-13 में पाकिस्तान ने किया था भारत का दौरा

अखबार ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर सीरीज की शुरुआत होती है, तो भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछली बार जब 2012-13 में दोनों टीमों के बीच द्विपक्षीय सीरीज हुई थी, तो पाकिस्तान टीम ने भारत का दौरा किया था।

ICC टी-20 वर्ल्ड कप 2016 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। यह दोनों देशों के बीच आखिरी टी-20 मुकाबला है।

ICC टी-20 वर्ल्ड कप 2016 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। यह दोनों देशों के बीच आखिरी टी-20 मुकाबला है।

ICC के चेयरमैन ने सीरीज से किया इनकार: हालांकि, ICC के चेयरमैन एहसान मनी ने इससे साफ इनकार कर दिया। एक चैनल पर इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि इस सीरीज को लेकर अभी तक किसी ने भी उनसे संपर्क नहीं किया है और न ही इस संबंध में भारतीय बोर्ड ने उनसे बातचीत की है। दिलचस्प बात तो यह है कि इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज के 5वें मैच के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कुछ और टी-20 सीरीज की बात कही थी। विराट ने बताया था कि बोर्ड इस साल वर्ल्ड कप से पहले कुछ और टी-20 सीरीज आयोजित करने की सोच रहा है। टीम इंडिया का शेड्यूल फिलहाल काफी टाइट है। 9 अप्रैल से IPL का 14वां सीजन खेला जाना है, जो कि 30 मई को खत्म होगा। इसके बाद टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 से 22 जून तक होने वाले ICC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल खेलने के लिए इंग्लैंड जाना है।

जुलाई या सितंबर लास्ट में हो सकती है टी-20 सीरीज

वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के बाद जुलाई में भारत के पास एक महीने का फ्री समय होगा। भारत-पाकिस्तान सीरीज के लिए इस विंडो का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद अगस्त में भारत को इंग्लैंड के खिलाफ ही 5 टेस्ट की सीरीज भी खेलनी है। यह सीरीज 14 सितंबर को खत्म होगी। इंग्लैंड सीरीज के बाद और अक्टूबर में शुरू हो रहे वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के पास करीब 1 महीने का समय रहेगा। इस विंडो को भी दोनों के बीच टी-20 सीरीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत और पाकिस्तान ने 9 साल से कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली। दोनों ने 2007-08 सीजन के बाद से टेस्ट सीरीज में भी एक-दूसरे का सामना नहीं किया है। हालांकि, दोनों टीमें ICC टूर्नामेंट्स में एक-दूसरे के खिलाफ खेलती रही हैं। दोनों के बीच आखिरी टी-20 मुकाबला 19 मार्च, 2016 को हुआ था। तब ICC टी-20 वर्ल्ड कप के इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था।